



● CDR से लेकर खाते तक की होगी जांच, 'मास्टरमाइंड' की भी तलाश

DBD

दो बजे दोपहर

पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है

▶ बयान पर सियासी पारा हाई

▶ विपक्ष ने की तोड़फोड़ की निंदा

▶ शिवसेना ने बताया स्वाभाविक प्रतिक्रिया

अब सरकार खंगालेगी कुणाल की कुंडली

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा विवादों में घिर गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), बैंक खातों और अन्य गतिविधियों की जांच का आदेश दिया है। गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि सरकार इस घटनाक्रम के पीछे के 'मास्टरमाइंड' को भी बेनकाब करेगी। गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधान परिषद में ऐलान किया कि कामरा की कॉल डिटेल, बैंक खातों और अन्य स्रोतों की गहन जांच होगी। महाराष्ट्र पुलिस उनकी लोकेशन ट्रैक कर रही है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है।

कुणाल कामरा ने क्या दिया था बयान?

कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने शो में महाराष्ट्र के डिटी सीएम एकनाथ शिंदे पर उनका नाम लिए बिना विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बिना नाम लिए कटाक्ष करते हुए उन्हें गद्दार बोला था। इस विवादित टिप्पणी को लेकर कुणाल कामरा पर केस भी दर्ज किया गया है।

विवादित बयान के बाद जमकर हुआ बवाल

वहीं इस विवादित बयान के बाद भड़के शिवसैनिकों ने जहां शो का आयोजन किया गया था, वहां धावा बोल दिया। जानकारी के मुताबिक, मुंबई के खार इलाके में होटल युनिकॉन्टिनेंटल में शिवसेना के कार्यकर्ताओं की ओर से तोड़फोड़ की गई। इसके बाद शिवसेना युवा

सेना (शिंदे गुट) के महासचिव राहुल कनाल और 12 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और उसके बाद गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही तोड़फोड़ मामले में सभी 12 आरोपियों को जमानत दे दी गई।

बयान पर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा



महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की व्यंग्यात्मक टिप्पणी को लेकर सोमवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। शोरशराबे के चलते अध्यक्ष राहुल नावकर ने सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी। बाद में जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, तो CM फडणवीस ने आश्वासन दिया कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी।

क्या बोले सत्तापक्ष के नेता?

शिंदे गुट के विधायक अर्जुन खोतकर ने कहा कि कामरा पहले भी प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी कर चुके हैं। ऐसे में उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा विधायक प्रवीण दरेकर ने विधान परिषद में कामरा को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। सीएम फडणवीस ने कहा कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई सुपारी लेकर हमारा अपमान करता है, तो कार्रवाई जरूर होगी।

विपक्ष का पलटवार

नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने कहा कि कामरा ने जो कहा, वह सत्य है और इसे मजाकिया लहजे में लिया जा सकता था। लेकिन इसके बजाय खार में होटल में तोड़फोड़ की गई, जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़ी। ऐसे में कार्रवाई तोड़फोड़ करने वालों पर होनी चाहिए, न कि कामरा पर।

कुणाल कामरा ने माफी से किया इनकार

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई व्यंग्यात्मक टिप्पणी को लेकर माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए माफी का सवाल ही नहीं उठता। मुंबई पुलिस से फोन पर हुई बातचीत में कामरा ने कहा कि मैं तमिलनाडु में हूँ, मैं किसी से सुपारी नहीं ली। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट कहेगा तो माफी मांग लूंगा, लेकिन अभी नहीं।

बीएमसी ने स्टूडियो को किया धराशायी

मुंबई के खार स्थित हैबिटेड स्टूडियो को सोमवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने कथित निर्माण उल्लंघन के कारण ध्वस्त कर दिया। बीएमसी की यह कार्रवाई शिवसैनिकों द्वारा रविवार देर रात स्टूडियो और होटल में तोड़फोड़ किए जाने के एक दिन बाद की गई। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि होटल के बेसमेंट में बनाए गए अस्थायी शेड और अन्य संरचनाओं को हटाया गया, क्योंकि इनका निर्माण बिना नगर निगम की अनुमति के किया गया था। अधिकारी ने यह भी बताया कि अब बीएमसी होटल की जांच करेगी कि सब कुछ अनुमत योजना के अनुसार है या नहीं।

न्यूज़ ग्रीफ

इमारत में भीषण आग, एक की मौत, 3 घायल



मुंबई। विद्याविहार रेलवे स्टेशन के सामने स्थित एक 13 मंजिला इमारत में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। इसमें दो सुरक्षा गार्ड सहित चार लोग झुलस गए जिसमें से एक मौत हो गई। आग में झुलसे तीन लोगों का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इमारत में आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग और पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और इमारत में फंसे 15-20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसकी वजह से कई लोगों की जान बच गई। नीलकंठ किंगडम कॉम्प्लेक्स में सोमवार सुबह करीब 4.35 बजे आग लगी थी। ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई आग ने पहली और दूसरी मंजिल के फ्लैट को भी अपनी जड़ में ले लिया था। आग में सात फ्लैट जलकर खाक हो गए हैं।

'जीवित सातबारा' विशेष अभियान 1 अप्रैल से लागू

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार राज्य के सभी जिलों में 'जीवित सातबारा' विशेष अभियान 1 अप्रैल से शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत सातबारा (7/12 भूमि अधिलेख) से मृतक खाताधारकों के नाम हटाए जाएंगे और जीवित खातेदारों को उत्तराधिकारी पंजीयन अधिलेख में नाम अपडेट करने का अधिकार मिलेगा। विधान परिषद में राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मृतक खाताधारकों के नाम हटाने की प्रक्रिया जटिल होने के कारण उनके परिवजनों को तहसील कार्यालयों के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं।

देवभाऊ के योगी मॉडल पर रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो आरोपियों के घरों को गिराने पर रोक लगाई, प्रशासन को लगाई फटकार

▶ कोर्ट का आदेश आने से पहले दंगे के आरोपी फहीम खान का घर जमींदोज

डीबीडी संवाददाता | मुंबई/नागपुर

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने नागपुर हिंसा मामले में दो आरोपियों के घरों को गिराने की प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में प्रशासन के रवैये को मनमाना और दमनकारी बताते हुए कड़ी फटकार भी लगाई। बता दें कि, नागपुर में हुई हिंसा के बाद स्थानीय प्रशासन ने आरोपियों के घरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी, जिसे लेकर अदालत में चुनौती दी गई थी। इस मामले की अगली सुनवाई जल्द होने की संभावना है।

भारी सुरक्षा में हुई थी तोड़फोड़

सोमवार सुबह पुलिस सुरक्षा में नगर निगम ने फहीम खान का घर गिराना शुरू किया। उनके घर को बिना इजाजत बनी अवैध इमारत बताया गया। वहीं दूसरे आरोपी यूसुफ शेख के घर का भी



एक अवैध हिस्सा तोड़ा जा रहा था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई रोक दी गई। बता दें कि, फहीम खान 'माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी' (एमडीपी) के नेता हैं।

आदेश से पहले ही तोड़ा गया फहीम का घर

हालांकि, कोर्ट का आदेश आने से पहले ही फहीम खान के दो मंजिला घर को तोड़ा जा चुका था। वहीं, कोर्ट के आदेश के बाद यूसुफ शेख के घर के अवैध हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई रोक दी गई। वहीं फहीम खान और यूसुफ शेख ने अपने घरों की तोड़फोड़ के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस पर जस्टिस नितिन साम्बरे और वृषाली जोशी की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने सवाल किया कि बिना सुनवाई के घरों को कैसे तोड़ा गया? फहीम खान के वकील अश्विन इंगोले ने बताया कि कोर्ट ने सरकार और नगर निगम से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। अगर तोड़फोड़ अवैध पाई गई, तो मुकसान की भरपाई प्रशासन को करनी होगी।

माननीयों की बल्ले-बल्ले

▶ पूर्व सांसदों की पेंशन बढ़ाकर 31 हजार की गई

एजेंसी | नई दिल्ली

सरकार ने सांसदों की सैलरी में 24% का इजाफा कर दिया है। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक मौजूदा सांसदों को अब 1.24 लाख रुपए प्रति माह मिलेगा। पहले उन्हें 1 लाख रुपए प्रति माह मिलते थे। यह बढ़ोतरी कॉस्ट इम्प्लेशन इंडेक्स (लागत मुद्रास्फीति सूचकांक) के आधार पर की गई है। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। इससे पहले मोदी सरकार ने 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों की हर पांच साल में समीक्षा का नियम बनाया था। यह समीक्षा महंगाई दर पर आधारित होती है। डेली अलाउंस और पेंशन भी बढ़ाई गई है। डेली अलाउंस 2 हजार रुपए से बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन 25 हजार रुपए से प्रति माह से बढ़ाकर 31 हजार रुपए प्रति माह कर दी गई है। पांच साल से ज्यादा समय तक सांसद रहे सदस्यों को हर साल के लिए मिलने वाली एक्स्ट्रा पेंशन भी 2 हजार रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है।

अधिसूचना के मुताबिक कहां, कितना बदलाव हुआ



एक सांसद को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के रूप में 87,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे, जबकि पहले यह 70,000 रुपए था। कार्यालय खर्च के लिए 75,000 रुपये मिलेंगे, जबकि पहले यह 60,000 रुपए था। इसमें कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए 50,000 और स्टेशनरी के लिए 25,000 रुपए शामिल हैं। कार्यकाल के दौरान एक बार 1 लाख रुपए का टिकाऊ फर्नीचर और 25,000 रुपए का गैर-टिकाऊ फर्नीचर खरीदने के लिए सुविधा मिलेगी।

2018 में बढ़ाया गया था सांसदों का वेतन

2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सांसदों का वेतन 50,000 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया था। जेटली ने हर पांच साल में वेतन और भत्तों को ऑटोमैटिक रिवाइज करने की व्यवस्था भी की थी, जिसके तहत इसे मुद्रास्फीति के मुताबिक किया जाता था। इस तरह सांसदों की सैलरी तय करने के लिए सिफारिशें करने की प्रथा

समाप्त हो गई। 2020 में, COVID-19 महामारी के दौरान सरकार ने एक साल के लिए सांसदों और मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती की थी। 2025 में की गई बढ़ोतरी आधिकारिक अधिनियम 1961 में दी गई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए की गई है।

सांसदों की सैलरी 24% बढ़ी, हर सांसद को अब 1.24 लाख मिलेंगे

माइक्रो प्लास्टिक पर रोक के लिए हाईकोर्ट सख्त

▶ केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने समुद्री जीवन और मानव स्वास्थ्य के लिए माइक्रो प्लास्टिक के खतरे को गंभीरता से लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पूछा है कि माइक्रो प्लास्टिक को नियंत्रित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति मकरंद कार्णिक की पीठ के समक्ष कंजरवेशन ऐक्शन ट्रस्ट की ओर से वकील रोनिता भट्टाचार्य ने हस्तक्षेप याचिका दायर की। याचिका में दावा किया गया है कि सूक्ष्म प्लास्टिक (5 मिमी से छोटे कण) मछलियों और अन्य समुद्री जीवों के शरीर में पहुंच रहे हैं, जिससे उनका जीवन संकट में है।

मानव जीवन के लिए भी खतरनाक



याचिका में कहा गया है कि प्लास्टिक के कंटेनरों में पैक खाद्य पदार्थ, बोतलबंद पानी, दूध के पाउच और दवाइयों के जरिए माइक्रो प्लास्टिक ईंसानों के शरीर में प्रवेश कर रहा है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। पीठ ने 4 अक्टूबर 2024 को प्लास्टिक कचरे की समस्या का संज्ञान लिया था। अदालत ने कहा कि माइक्रो प्लास्टिक समुद्र में जाता है और फिर किनारों पर लौट आता है। इसका असर पूरे मुंबई के समुद्री तटों पर पड़ रहा है।

पीएनबी घोटाला

सीबीआई ने दाखिल की पूरक चार्जशीट

▶ नीरव मोदी की बहन को बनाया आरोपी

मुंबई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में एक पूरक चार्जशीट दाखिल की है। जिसमें मुख्य आरोपी नीरव मोदी की बहन पूरवी मेहता को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने यह चार्जशीट विशेष सीबीआई अदालत में विशेष लोक अभियोजक ए. लिमोसिन के माध्यम से दाखिल की। चार्जशीट में पूरवी मेहता के अलावा फायरस्टार ग्रुप ऑफ कंपनियों के अधिकारी आदित्य नानावटी को भी आरोपी बनाया गया है। बेल्जियम की नागरिक पूरवी मेहता पर आरोप है कि उन्होंने पीएनबी से जारी किए गए लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए प्राप्त फंड का लाभ उठाया।

ईडी केस में सरकारी गवाह बने पूरवी और मयंक मेहता



इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूरवी और मयंक मेहता को आरोपी बनाया गया था। लेकिन अब दोनों इस केस में सरकारी गवाह बन चुके हैं। नीरव मोदी और उनके माता मेहुल चौकसी इस घोटाले के मुख्य आरोपी हैं।

डॉक्टरों की लापरवाही से हुई महिला की मौत

► विष्णुनगर पुलिस थाने में मामला दर्ज

डीबीडी संवाददाता । डॉंबिवली

शास्त्रीनगर नगरपालिका अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती कराई गई 26 वर्षीय सुवर्णा सरोदे की मौत के मामले में दो डॉक्टरों के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। मनपा जांच समिति की रिपोर्ट में आउटसोर्सिंग संस्था के डॉक्टरों को दोषी ठहराया गया, जिसके बाद विष्णुनगर पुलिस ने डॉ. संगीता पाटिल और डॉ. मीनाक्षी केंद्र के खिलाफ IPC की धारा 106(1) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।



सिजेरियन के बाद बिगड़ी तबीयत, दो दिन में मौत

सुवर्णा सरोदे पहले से सिजेरियन डिलीवरी करा चुकी थीं और इस बार भी डॉक्टरों ने उन्हें सीजेरियन करने का फैसला लिया। लेकिन ऑपरेशन के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और गर्भाशय से लगातार रक्तस्राव होने लगा। स्थिति गंभीर होने पर उनका गर्भाशय निकालना पड़ा, लेकिन दो दिन बाद उनकी मौत हो गई।

मनपा अस्पतालों की सेवाओं पर सवाल

इस घटना के बाद मनपा अस्पतालों की चिकित्सा सेवाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नागरिकों में नाराजगी है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही जा रही है। फिलहाल, सहायक पुलिस निरीक्षक प्रशांत मोरे मामले की जांच कर रहे हैं और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मनपा जांच रिपोर्ट और कार्रवाई

घटना की गंभीरता को देखते हुए मनपा आयुक्त डॉ. इंदुरानी जाखड़, उपायुक्त प्रसाद बोरकर और जिला सर्जन कैलाश पवार की देखरेख में जांच समिति का गठन किया गया। रिपोर्ट में डॉ. संगीता पाटिल और डॉ. मीनाक्षी केंद्र की लापरवाही सामने आई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।

राजनीतिक और सामाजिक दबाव

ठाकरे गुट के नेता दीपेश म्हात्रे ने आउटसोर्सिंग संस्था को मनपा से बर्खास्त करने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। विधायक गोपालराव मते और मनोज शिंदे ने यह मामला विधानमंडल में उठाया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

गावदेवी मार्केट में कपड़े बैग वेंडिंग मशीनें स्थापित

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

प्लास्टिक बैग के उपयोग को रोकने और कपड़े के बैग को बढ़ावा देने के लिए ठाणे नगर निगम और



रोटरी क्लब ऑफ ठाणे नॉर्थ ने गावदेवी मार्केट, नौपाड़ा में दो कपड़े बैग वेंडिंग मशीनें स्थापित की हैं। अब ग्राहक 10 रुपये डालकर मशीन से कपड़े का थैला प्राप्त कर सकते हैं। सोमवार सुबह इन मशीनों का उद्घाटन ठाणे नगर निगम की मुख्य पर्यावरण अधिकारी मनीषा प्रधान और रोटरी जिला 3124 के प्रांतीय आयुक्त

दिनेश मेहता के हाथों हुआ। इस अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ ठाणे नॉर्थ की अध्यक्ष मेधा जोशी, सचिव अमोल नाले, जिला सचिव संतोष भिड़े सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

आगे भी लगेंगी मशीनें

मुख्य पर्यावरण अधिकारी मनीषा प्रधान ने बताया कि रोटरी क्लब के सहयोग से ठाणे के अन्य बाजारों में भी ऐसी वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। यह पहल प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

डोंबिवली रेलवे स्टेशन क्षेत्र में तुरंत पार्किंग शुरू करें, अन्यथा आंदोलन : ठाकरे गुट



डीबीडी संवाददाता । डॉंबिवली

डोंबिवली। शिवसेना (ठाकरे गुट) ने डोंबिवली पश्चिम रेलवे स्टेशन क्षेत्र में पार्किंग सुविधा बहाल करने की मांग की है। जिला प्रमुख दीपेश म्हात्रे के मार्गदर्शन में शहर प्रमुख प्रकाश तेलगोटे और अन्य कार्यकर्ताओं ने रेलवे प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए 10 दिनों के भीतर पार्किंग शुरू करने की चेतावनी दी है।

यात्रियों को हो रही परेशानी

पिछले कुछ महीनों से द्वारका होटल के पास रेलवे क्षेत्र में पार्किंग बंद होने के कारण महिलाओं, बुजुर्गों, छात्रों और यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दैनिक यात्रियों को गाड़ियां सड़क पर खड़ी करनी पड़ती हैं, जिससे यातायात जाम हो रहा है। रेलवे प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर तुरंत पार्किंग सुविधा बहाल करने की मांग की गई है। ठाकरे

गुट ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 10 दिन के भीतर पार्किंग सुविधा शुरू नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान शहर प्रमुख प्रकाश तेलगोटे, विभाग प्रमुख शाम चौगले, राजेंद्र सावंत, प्रकाश कदम, मंदार निकम, ऋतुनिल पावस्कर, शेखर चव्हाण, प्रिया दांडगे और सायली जगताप सहित कई शिवसैनिक मौजूद थे।

कुणाल कामरा के खिलाफ शिवसैनिकों का विरोध प्रदर्शन



डीबीडी संवाददाता । डॉंबिवली

डोंबिवली। स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना (शिंदे गुट) पर व्यंग्यात्मक गीत प्रस्तुत करने के बाद विवाद खड़ा हो गया। इस मामले को लेकर शिंदे गुट के शिवसैनिकों ने डोंबिवली में विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को शिवसेना (शिंदे गुट) के कार्यकर्ता डोंबिवली के इंदिरा चौक पर एकत्र हुए और कुणाल कामरा की तस्वीर पर काल्पनिक पोस्टर तथा चप्पल मारकर अपना गुस्सा जाहिर किया। इसके अलावा, रामनगर थाने में उनके खिलाफ शिकायत

दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने कामरा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

शिवसेना कार्यकर्ताओं की नाराजगी

शिंदे गुट के नेताओं का कहना है कि कामरा के व्यंग्यात्मक गीत का मकसद एकनाथ शिंदे की छवि खराब करना है। कल्याण ग्रामीण के जिला अध्यक्ष महेश पाटिल ने कहा कि हमारे नेता को जनता का समर्थन मिला है, जिसे विरोधी स्वीकार नहीं कर पा रहे। अब हास्य कलाकारों के जरिए उनकी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। विरोध प्रदर्शन में पूर्व नगरसेवक महेश पाटिल, विश्वनाथ राणे, संजय पावशे और दत्ता वझे समेत कई शिवसैनिक

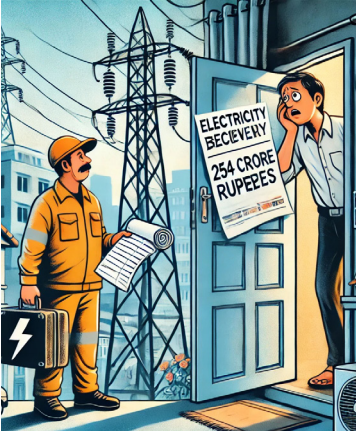
मुर्बाड के 500 चावल किसानों का रुका बोनस जल्द मिलेगा: मंत्री

मुंबई/ठाणे। मुर्बाड के 500 चावल किसानों को 2020-21 से मिलने वाला 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस अभी तक नहीं मिला है। विधायक संजय केलकर ने विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि ऑनलाइन पंजीकरण में बाधाओं के कारण किसानों का लाखों रुपये का बोनस रुका हुआ है।

सरकार का आश्वासन

मंत्री ने सदन में जवाब देते हुए स्वीकार किया कि बोनस रुका हुआ है। अब तक 3,263 किसानों का पंजीयन हो चुका है और उन्हें बोनस मिल गया है। शेष 500 किसानों को भी जल्द ही बोनस दिया जाएगा। वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है और यह मुद्दा कैबिनेट बैठक में रखा गया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही 79 लाख रुपये किसानों के खातों में जमा कर दिए जाएंगे।

कल्याण-भांडुप में 254 करोड़ रुपये की बिजली बिल वसूली की चुनौती



डीबीडी संवाददाता । कल्याण

कल्याण और भांडुप सर्किलों में बिजली उपभोक्ताओं से 254 करोड़ रुपये की बकाया और चालू बिजली बिल वसूली एक बड़ी चुनौती बन गई है। महावितरण ने उपभोक्ताओं से बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने की अपील की है, अन्यथा उनकी बिजली आपूर्ति काटी जा सकती है। मार्च माह के अंत को देखते हुए बिजली कर्मचारियों को तेज गर्मी में भी वसूली अभियान तेज करना पड़ा है।

क्षेत्रवार बकाया राशि

कल्याण संभाग के अंतर्गत चार संभागीय कार्यालयों को 118.55 करोड़ रुपये की वसूली करनी है, जिसमें मार्च 2024 तक 1.21 करोड़ रुपये और अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच 22.16 करोड़ रुपये का बकाया शामिल है। वहीं, भांडुप विभाग में ठाणे, वाशी और पेण क्षेत्रों में 135.31 करोड़ रुपये की वसूली शेष है, जिसमें 76.94 करोड़ रुपये का पुराना बकाया शामिल है।

महावितरण का सख्त रुख और उपभोक्ताओं के लिए सुविधा

महावितरण ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिजली बिल भुगतान केंद्र रविवार और अन्य छुट्टियों पर भी खुले रखने की घोषणा की है। साथ ही, ऑनलाइन भुगतान विकल्पों जैसे महावितरण वेबसाइट, मोबाइल ऐप, डेबिट/क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। कंपनी ने सभी ग्राहकों से समय पर भुगतान करने की अपील की है ताकि बिजली आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आए।

शिंदे गुट की महिला कार्यकर्ता ने पूर्व नगरसेवक को बीच सड़क पर पीटा



एजेंसी । कल्याण

महाराष्ट्र के कल्याण में एक चौकाने वाली घटना सामने आई है, जहां शिवसेना शिंदे गुट की महिला कार्यकर्ता रानी कपोते ने पूर्व नगरसेवक मोहन उगले को बीच सड़क पर थपड़ों से पीट दिया। घटना का वीडियो मोबाइल में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

क्या है मामला ?

जानकारी के मुताबिक, एक सड़क निर्माण कार्य के भूमिपूजन को लेकर मोहन उगले और रानी कपोते के बीच विवाद हुआ। महिला कार्यकर्ता रानी कपोते का आरोप है कि मोहन उगले ने बहस के दौरान उनके शरीर को शर्मनाक तरीके से छुआ, जिसके बाद उन्होंने गुस्से में आकर पूर्व नगरसेवक की पिटाई कर दी।

मोहन उगले का बयान

पूर्व नगरसेवक मोहन उगले ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महिलाओं को कानून द्वारा सुरक्षा प्राप्त है। हमने उस महिला को अब तक कुछ नहीं कहा है और न ही कुछ कहेगे, लेकिन पार्टी को ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

गोरेवाडा जू में बाघों और तेंदुए की मौत बर्ड फ्लू से, अंतिम रिपोर्ट का इंतजार

मुंबई/नागपुर। बालासाहेब ठाकरे गोरेवाडा अंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय में तीन बाघों और एक तेंदुए की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई है। हालांकि, इस संबंध में भोपाल के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान की अंतिम रिपोर्ट अभी नहीं आई है। महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाईक ने विधान परिषद में यह जानकारी दी और आश्वासन दिया कि रिपोर्ट मिलने के बाद सदन में पेश की जाएगी। शिवसेना (शिंदे गुट) की विधायक मनीषा कायदे ने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में कई पशु चिकित्सक मंत्रियों के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) बनाए गए हैं, जिससे वन्य प्राणियों की देखभाल में कमी आ रही है। इस पर वन मंत्री ने कहा कि वे मंत्री कार्यालयों में पशु चिकित्सकों की नियुक्ति की जानकारी लेंगे और उन्हें वन्य प्राणियों की सेवा में लौटने की सलाह देंगे।



तुलिन पुलिस ने निकाला रूट मार्च

डीबीडी संवाददाता । नालासोपारा मीरा-भयंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय के आदेशानुसार, नालासोपारा के तुलिन पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय जाधव व सहयोगी अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा क्षेत्र में रूट मार्च किया गया। नालासोपारा तुलिन पुलिस

थाने से सेंट्रल पार्क, ओसवाला, रहमत नगर, नागिनदास, विरार रोड होते हुए अधिकारी तुलिन थाने में पहुंचे। इस दौरान पुलिस बल के जवानों को दंगा नियंत्रित करने तथा आपातकालीन स्थिति को समझते हुए इसे काबू कैसे करें, इसके मार्च किया गया।

यौन शोषण से तंग आकर सौतेले पिता पर हमला

► गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

नालासोपारा के संतोष भुवन इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 24 वर्षीय युवती ने अपने सौतेले पिता का चाकू से गुतांग काट दिया। यह घटना सोमवार दोपहर करीब तीन बजे हुई। आरोपी युवती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि गंभीर रूप से घायल सौतेले पिता को मुंबई के शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।



लगातार शारीरिक शोषण से तंग थी युवती

पुलिस के मुताबिक, आरोपी युवती की मां ने दूसरी शादी की थी। उसका 45 वर्षीय सौतेला पिता पिछले एक साल से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। सोमवार को जब उसने फिर जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो युवती ने आत्मरक्षा में उस पर हमला कर दिया।

पुलिस ने युवती को हिरासत में लिया

सोमवार को युवती ने पहले सौतेले पिता की आंख पर पट्टी बांध दी और फिर चाकू से उसके गुतांग पर हमला कर दिया। दर्द से तड़पते हुए वह व्यक्ति घर से बाहर भागा, लेकिन युवती ने उसका पीछा किया और सड़क पर भी हमला किया। इस घटना को अंजाम देने के बाद युवती खून से सने चाकू के साथ सड़क पर घूम रही थी। इसकी सूचना मिलते ही तुलिन पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने घायल सौतेले पिता को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी स्थिति बिगड़ती देख उसे मुंबई के शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तुलिन पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय जाधव ने बताया कि सौतेला पिता युवती से दुराचार की वारदात को अंजाम दे रहा था। इससे नाराज युवती ने जानलेवा हमला किया है।

चारकोल प्रतिबंध पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मांगा एमपीसीबी से जवाब

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या चारकोल (काठकोयला) स्वीकृत ईंधन की श्रेणी में आता है और यह प्रदूषणकारी नहीं है। अदालत ने एमपीसीबी को 21 अप्रैल तक इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। बॉम्बे चारकोल व्यवसाय एसोसिएशन (बीसीएमए) की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति मकरंद कार्णिक की पीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने चारकोल को स्वीकृत ईंधन की मानक सूची में शामिल किया है, लेकिन महाराष्ट्र में इसे प्रतिबंधित करने की कोशिश की जा रही है।



चारकोल और कोयले को लेकर विवाद

याचिकाकर्ताओं के वकील प्रेरक चौधरी ने दलील दी कि एमपीसीबी और बीएमसी ने 9 जनवरी के हाईकोर्ट आदेश की गलत व्याख्या की, जिसमें लकड़ी और कोयले पर चलने वाली बेकरी को छह महीने के भीतर हरित ईंधन में परिवर्तित करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा कि चारकोल को कोयले जैसा मानकर बेकरी और होटलों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जबकि चारकोल कोयले की तरह प्रदूषणकारी नहीं है।

एमपीसीबी को देना होगा स्पष्टीकरण

एमपीसीबी के वकील आशुतोष कुंभकोनी ने कहा कि नोटिस में कोयले का जिक्र किया गया था, न कि चारकोल का। उन्होंने सुझाव दिया कि एक विशेषज्ञ समिति इस मुद्दे पर विचार कर सकती है। हाई कोर्ट ने कहा कि एमपीसीबी चारकोल को स्वीकृत ईंधन की सूची में शामिल करने और इसके प्रदूषण स्तर पर निर्णय लेने से पहले व्यवसायियों को सुनवाई का अवसर दे। अदालत ने एमपीसीबी और राज्य सरकार को 21 अप्रैल से पहले अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

उल्हासनगर मनपा का बजट पेश

जल कर और पूंजी मूल्य आधारित कर प्रणाली पर जोर

डीबीडी संवाददाता । उल्हासनगर

उल्हासनगर महानगरपालिका ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 988.72 करोड़ रुपये का बजट सोमवार को पेश किया। इस बजट में 988.18 करोड़ रुपये का व्यय और 54 लाख रुपये की शेष राशि का प्रावधान किया गया है।



राजस्व बढ़ाने के प्रयास

मनपा की करीब 900 करोड़ रुपये की देनदारियों को देखते हुए प्रशासन ने संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन, व्यापार लाइसेंस नीति, विज्ञापन और होटिंग दरों में बदलाव सहित कई कदम उठाने का निर्णय लिया है। जल मीटर लगाने का भी प्रस्ताव है, ताकि जल उपयोग के आधार पर शुल्क लिया जा सके। आयुक्त मनीषा अहवाल ने बजट को स्मार्ट और पर्यावरण हितैषी बनाने पर जोर दिया है, जिससे नगर पालिका की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के साथ-साथ शहर का विकास किया जा सके।

महत्वपूर्ण घोषणाएं

- जल कर में वृद्धि : कई वर्षों से जल शुल्क नहीं बढ़ाया गया था, जिसे इस वर्ष से लागू किया जाएगा।
- पूंजी मूल्य आधारित कर प्रणाली : संपत्ति कर में वृद्धि किए बिना नई कर प्रणाली अपनाने का संकेत।
- स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर :सड़कें, चौराहे, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पार्क, शौचालय, कब्रिस्तान आदि को अपग्रेड किया जाएगा।
- पर्यावरणीय सुधार : इलेक्ट्रिक बसों के लिए 4 करोड़ रुपये, सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए 1 करोड़ रुपये, एलईडी लाइट प्रतिस्थापन के लिए 3.5 करोड़ रुपये और हरित परियोजनाओं के लिए 6.5 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- सीवेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट :5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पवई में सड़क पर दिखा मगरमच्छ



डीबीडी संवाददाता । मुंबई

आईआईटी मुंबई के पवई इलाके में रविवार देर रात करीब छह फीट लंबा मगरमच्छ खुलेआम घूमता हुआ नजर आया, जिससे स्थानीय निवासियों में डर का माहौल बन गया। हालांकि, कई लोग मगरमच्छ की तस्वीरें और वीडियो लेने के लिए भीड़ में जुट गए। आईआईटी बॉम्बे का परिसर बोरीवली के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और पवई झील से सटा हुआ है, जिससे यहां अक्सर वन्यजीव देखे जाते हैं। तेंदुए नजर आने की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन अब मगरमच्छों का

खुले में घूमना चिंता बढ़ा रहा है। रविवार रात झील क्षेत्र में पंचावती मंदिर के पास सड़क पर मगरमच्छ देखा गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना सुरक्षा गार्डों को दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ देर बाद मगरमच्छ वापस झील में चला गया। पवई झील में मगरमच्छों की संख्या पवई झील मगरमच्छों का एक प्रमुख ठिकाना है। जुलाई 2022 में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारा कराई गई गणना में झील में 18 वयस्क मगरमच्छों की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी।

आखिरकार प्रशांत कोर्टकर को लगी हथकड़ी

कोल्हापुर पुलिस ने तेलंगाना से किया गिरफ्तार

मुंबई/कोल्हापुर। इतिहासकार इंद्रजीत सावंत को धमकाने और छत्रपति शिवाजी महाराज व छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के आरोपी प्रशांत कोर्टकर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। वह कई दिनों से फरार था, जिसे कोल्हापुर पुलिस ने सोमवार को तेलंगाना से दबोच लिया।



क्या है मामला?

प्रशांत कोर्टकर पर आरोप है कि उन्होंने इंद्रजीत सावंत को फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में कोल्हापुर और नागपुर में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। महाराष्ट्रभर में कोर्टकर के बयान का विरोध हुआ, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठी।

जमानत याचिका रद्द होने के बाद गिरफ्तारी

11 मार्च को कोल्हापुर अदालत ने कोर्टकर की अग्रिम जमानत मंजूर की थी। सामाजिक संगठनों के विरोध के बाद कोल्हापुर पुलिस ने अदालत से जमानत रद्द करने की मांग की। अदालत ने जमानत रद्द कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश तेज कर दी।

भागने की अटकलें, फिर गिरफ्तारी

शुरुआत में कहा जा रहा था कि कोर्टकर पश्चिम बंगाल और फिर दुबई भाग गया। लेकिन बाद में उनकी पत्नी ने उनका पासपोर्ट जमा करा दिया, जिससे यह साफ हो गया कि वह देश से बाहर नहीं गए थे।

सबूत नष्ट करने की कोशिश

कोर्टकर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने मोबाइल फोन का सारा डेटा डिलीट कर दिया। इस पर इंद्रजीत सावंत ने सबूत नष्ट करने की साजिश

का मामला दर्ज करने की मांग की। कोल्हापुर पुलिस ने नागपुर स्थित उनके आवास पर भी छानबीन की थी।

महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को ‘भारत रत्न’ देने की सिफारिश



डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र विधानसभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को मरणोपरांत ‘भारत रत्न’ से सम्मानित करने की सिफारिश की। यह प्रस्ताव वाणिज्य एवं प्रोटेक्टॉल मंत्री जयकुमार रावल ने पेश किया, जिसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के छगन भुजबल और कांग्रेस के विजय वडेटीवार ने समर्थन दिया।

फडणवीस और अजित पवार का समर्थन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महात्मा की उपाधि देश में सर्वोच्च थी, जिसे केवल महात्मा फुले और महात्मा गांधी को ही प्राप्त हुआ। ‘भारत रत्न’ देना उनकी विरासत को मान्यता देने का कार्य होगा। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने इस प्रस्ताव को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह पुरस्कार उनकी महान सेवा की गरिमा को बढ़ाएगा।

ऊर्जा विभाग के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी

दीपक पवार | मुंबई

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को मुंबई में ऊर्जा विभाग के तहत महावितरण, महानिर्मित, महापारेषण और महाऊर्जा कंपनियों के पहले 100 दिनों के प्रदर्शन पर आधारित प्रगति पुस्तिका का विमोचन किया।

‘वन हंड्रेड डेज फॉर ट्वेंटी-फाइव इयर्स’ पुस्तक का विमोचन

महावितरण के स्वतंत्र निदेशक विश्वास पाटक द्वारा लिखित पुस्तक ‘वन हंड्रेड डेज फॉर ट्वेंटी-फाइव इयर्स’ में ऊर्जा क्षेत्र की दीर्घकालिक जरूरतों और पहले 100 दिनों में हासिल किए गए लक्ष्यों का विवरण दिया गया है। पुस्तक का विमोचन एमएसईबी होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में हुआ। इस मौके पर ऊर्जा राज्य मंत्री मेघना साकोरे बोर्डिकर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, महावितरण के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक लोकेश चंद्र, महापारेषण के अध्यक्ष संजीव कुमार, महानिर्मित के अध्यक्ष राधाकृष्णन बी., मुख्यमंत्री के सचिव अश्विनी भिडे समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।



बिजली दरों में कमी का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि सरकार के पहले 100 दिनों में महावितरण ने महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग में बिजली दरें कम करने का प्रस्ताव दायर किया है। राज्य की ऊर्जा परिवर्तन योजना के तहत नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया गया है, जिससे बिजली खरीद लागत में कमी आएगी और बिजली दरों को प्रभावी ढंग से पूरा करना है और यह रिपोर्ट कार्ड उसी दिशा में एक कदम है।

महाराष्ट्र में ठाई महीने में सांप्रदायिक तनाव की 800 से अधिक घटनाएं

सोशल मीडिया सबसे ज्यादा जिम्मेदार

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र में इस साल जनवरी से अब तक 823 सांप्रदायिक घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नागपुर में हुई हिंसा, औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग और सोशल मीडिया पर फैलाई गई झूठी खबरों के कारण राज्य में कई जगहों पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है। हाल ही में नंदुरबार, पुणे (ग्रामीण), रत्नागिरी, सांगली, बीड और सतारा जैसे जिलों में भी सांप्रदायिक घटनाएं दर्ज की गई हैं। राज्य में इस साल अब तक 4,836 हिंदू-मुस्लिम से जुड़े विवाद सामने आए, जिनमें से 170 मामले गंभीर और 3,106 गैर-गंभीर थे।



मस्जिद के पास हंगामा

रत्नागिरी के राजापुर में होली के जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने कथित रूप से मस्जिद के सामने नारेबाजी की और गेट को नुकसान पहुंचाया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। हालांकि, स्थानीय लोग इसे अपवाद मानते हैं और कहते हैं कि कोंकण क्षेत्र में हमेशा से हिंदू-मुस्लिम सौहार्द रहा है।

नागपुर में हिंसा और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट

17 मार्च को नागपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद कुछ इलाकों में हिंसा भड़क गई। इस दौरान सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों ने भी स्थिति को और बिगाड़ दिया। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने 144 भड़काऊ पोस्ट की पहचान की, जिनमें से 37 लिंक हटाए गए और 107 पर कार्रवाई की गई।।

कोंकण में हिंदू-मुस्लिम एकता की परंपरा

राजापुर के रहने वाले मुन्ना सुरवे ने बताया कि वहां हिंदू और मुस्लिम त्योहारों को मिलकर मनाने की परंपरा रही है। ईद पर हिंदू अपने मुस्लिम दोस्तों के घर जाते हैं, वहीं गणेश उत्सव, होली और पालखी जुलूस में मुस्लिम भी शामिल होते हैं।

अवमानना याचिका पर महाराष्ट्र प्राधिकरण को 'सुप्रीम' नोटिस

देश विरोधी नारों पर हुई थी ध्वस्तिकरण कार्रवाई

डीबीडी संवाददाता | मुंबई/नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अवमानना याचिका पर महाराष्ट्र प्राधिकरण से जवाब मांगा। दरअसल, कोर्ट सिंधुदुर्ग जिले में एक घर और दुकान के खिलाफ ध्वस्तिकरण की कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई क्रिकेट मैच के दौरान कथित भारत विरोधी नारे लगाने के मामले में की गई थी। इसी मामले में अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली याचिका पर महाराष्ट्र प्राधिकरण से जवाब मांगा गया है।



दुकान और घर को अवैध बताते हुए ध्वस्त कर दिया

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि रात करीब 9.15 बजे जब शिकायतकर्ता अपने दोस्त के घर जा रहा था, तो याचिकाकर्ता के बेटे ने क्रिकेट मैच देखते हुए भारत विरोधी नारा लगाया। याचिकाकर्ता और उसके नाबालिग बेटे को आधी रात को पुलिस स्टेशन

ले जाया गया और लड़के को चार-पांच घंटे बाद जाने दिया गया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी को जेल भेज दिया गया, लेकिन अधिकारियों ने 24 फरवरी को उसकी टिन शेड वाली कबाड़ की दुकान और घर को अवैध बताते हुए ध्वस्त कर दिया।

याचिकाकर्ता का दावा, पीठ की टिप्पणी

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि पिछले महीने टैपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के दौरान कथित भारत विरोधी नारे लगाने के बारे में एक तुच्छ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद अधिकारियों की ओर से तोड़फोड़ की गई। न्यायमूर्ति बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, ‘नोटिस जारी करें’। पीठ ने कहा कि याचिका पर चार सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी।

13 नवंबर, 2024 के फैसले का उल्लंघन करने का आरोप

सिंधुदुर्ग जिले के रहने वाले याचिकाकर्ता ने दावा किया कि टैपियंस ट्रॉफी में भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने के लिए उसके, उसकी पत्नी और उसके 14 वर्षीय बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद 24 फरवरी को उसका घर और दुकान ध्वस्त कर दी गई थी। मैच में भारत ने पिछले दिन जीत दर्ज की थी। किताबुल्ला हमीदुल्ला खान की ओर से दायर याचिका में मालवन नगर परिषद के मुख्य अधिकारी और प्रशासक के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि यह कार्रवाई संपत्तियों को ध्वस्त करने के संबंध में शीर्ष अदालत के 13 नवंबर, 2024 के फैसले का उल्लंघन है। फैसले में अखिल भारतीय दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए थे। इसमें बिना पूर्व कारण बताओ नोटिस और पीठिन पक्ष को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिए बिना संपत्तियों को ध्वस्त करने पर रोक लगाई गई थी।

महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने पेश हुए समय रैना

मुंबई। यूट्यूबर और कॉमेडियन समय रैना सोमवार को महाराष्ट्र साइबर सेल के अधिकारियों के सामने पेश हुए। उन्हें शो ‘इंडियाज गॉट तैलेंट’ से जुड़े मामले के सिलसिले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। कार्यालय से बाहर निकलते हुए स्टैडअप कॉमेडियन की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं।

महाराष्ट्र साइबर सेल लगातार समय रैना को समन भेज रहा था। पिछले दिनों भी इस स्टैडअप कॉमेडियन को महाराष्ट्र साइबर सेल ने तीसरी बार समन भेजा था। अब जाकर समय रैना साइबर सेल के अधिकारियों के सामने पेश हुए। यहां पर उन्हें ‘इंडियाज गॉट तैलेंट’ में की गई अश्लील टिप्पणी और उससे जुड़े मामले में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था।

समय रैना को जिस मामले में बयान दर्ज कराने के लिए महाराष्ट्र साइबर सेल ने बुलाया है, उसकी शुरुआत कुछ महीने पहले हुई। समय रैना एक शो ‘इंडियाज गॉट तैलेंट’ चलाते हैं, इस शो पर अलग-अलग तरह का हुनर दिखाने के लिए प्रतियोगी आते हैं। ऐसे ही एक शो में बतौर जज यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया भी नजर आए। उन्होंने शो में माता-पिता को लेकर विवादित और अश्लील टिप्पणी की। इसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मंच गया। साथ ही समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया के अलावा कुछ और लोगों पर पुलिस में शिकायत दर्ज हुई। कोर्ट तक ने इन्हें स्टैडअप कॉमेडियन की हदें समझाईं। समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया के अलावा अप्रवां मुख्डीना, यूट्यूबर आशीष चंचलानी और जसप्रीत सिंह भी इस विवाद का हिस्सा रहे हैं। इन पर भी अलग-अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज हुईं। इस पूरे विवाद का असर ये हुआ है कि समय रैना के कई शो कैसिल हो चुके हैं। उन्हें अपने शो का रिकंउ भी दर्शकों को वापस देना पड़ा है।

'परेल में यात्री टर्मिनल के लिए DPR मंजूरी पर में देरी क्यों?'

संसद की लोक लेखा समिति ने रेलवे से पूछा सवाल

मुंबई/नई दिल्ली। संसद की लोक लेखा समिति ने मुंबई के परेल में यात्री टर्मिनल बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी देने में देरी के लिए रेल मंत्रालय से सवाल किया है। समिति ने यह भी कहा कि मंत्रालय मध्य रेलवे के परेल वर्कशॉप में कोच नवीनीकरण इकाई स्थापित करने में अपने मानदंडों का पालन करने में विफल रहा, जिस पर 22.07 करोड़ रुपये का अवांछित व्यय हुआ, जिसके बाद उसने यात्री टर्मिनल बनाने का फैसला किया।

लोक लेखा समिति ने रिपोर्ट में क्या कहा?



संसद में 21 मार्च को पेश की गई एक रिपोर्ट में लोक लेखा समिति ने कहा कि रेल मंत्रालय के मानदंडों (अगस्त 1980 और फरवरी 1985 में जारी) में कहा गया है कि निविदाएं

आमंत्रित करने से पहले सभी क्षेत्रीय रेलवे को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे टेकेंडर को कार्य स्थल और आपूर्ति योजना सौंपने की स्थिति में हैं।

2007 में बनी योजना, अब तक अधूरी

2007-08 में मध्य रेलवे ने परेल वर्कशॉप में हर महीने 25 ब्रॉड गेज कोच मरम्मत करने की योजना बनाई। इसकी लागत 30.24 करोड़ रुपये तय हुई थी। 2010 में पहला ठेका 6.89 करोड़ रुपये में

यूनिटी कंस्ट्रक्शन, मुंबई को दिया गया, लेकिन फंड की कमी और जमीन न मिलने के कारण 2014 में यह रद्द करना पड़ा। तब तक 4.58 करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे। 2015 में बचा हुआ काम पूरा करने के लिए

5.94 करोड़ रुपये का नया ठेका पृथ्वी कंस्ट्रक्शन, मुंबई को दिया गया। लेकिन जमीन न मिलने के कारण यह काम भी पूरा नहीं हो सका और 2018 में इसे भी रद्द कर दिया गया।

रेलवे की सफाई, समिति ने मांगी पूरी जानकारी

वहीं इस पर रेल मंत्रालय ने कहा कि आगे से टेंडर जारी करने से पहले यह पक्का किया जाएगा कि काम के लिए जरूरी जगह उपलब्ध हो। समिति ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि जब पहली कंपनी समय पर काम पूरा नहीं कर पाई, तो दूसरी कंपनी को ठेका क्यों दिया गया? अब समिति ने रेलवे से परेल टर्मिनस के पहले चरण की योजना और डीपीआर मंजूरी में हो रही देरी की पूरी जानकारी देने को कहा है।

अब यात्री टर्मिनल बनाने की योजना, लेकिन मंजूरी अटक

रेलवे ने परेल वर्कशॉप को बंद कर वहां यात्री टर्मिनल बनाने का फैसला किया। इसके लिए 24 फरवरी 2020 को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भेजी गई, लेकिन अब तक मंजूरी नहीं मिली। समिति ने मंत्रालय से पूछा कि डीपीआर को मंजूरी देने में इतनी देरी क्यों हो रही है? साथ ही मंत्रालय से यह भी पूछा कि क्या नए यात्री टर्मिनल में ट्रेनों के संचालन की पूरी योजना बनी है?

मध्य रेल	
आर.ओ.बी. का निर्माण	
ई-निविदा (खुली निविदा) सूचना क्र. सी.ए.ओ.सी-04-2025 दिनांक: 21.03.2025	
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) मध्य रेल, छत्रपति माला, नया प्रशासनिक भवन, डी.एन. रोड, सीएसएमटी मुंबई-400001, कृते एवं भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रतिष्ठित ठेकेदारों से ई-निविदा (दो पैकेट प्रणाली में) के माध्यम से निम्नलिखित कार्य हेतु खुली निविदाएं आईआईटीएस वेबसाइट www.iimps.gov.in (ई-टेंडर पोर्टल) पर आमंत्रित करले हैं। कार्य का नाम: निविदाएं (दो पैकेट प्रणाली में)। निविदा की लागत: रु. 117,30,42,541.46 बयाना जमा राशि: रु. 60,15,200.00 निविदा फार्म की लागत: लागू नहीं (जीसीसी अप्रैल 2022 पृष्ठ 4 पर खंड संख्या 3 के अनुसार) ऑफर की वेधता: निविदा खुलने की तिथि से 90 दिनों पूर्णवधि: मानसून अवधि सहित 18 (अठारह) महीने निविदा दस्तावेजों की उपलब्धता: उपरोक्त कार्य के निविदा दस्तावेज www.iimps.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। निविदा प्रस्तुत करने और खोलने की तिथि व समय: संयुक्त: विधिवत भरी गयी ई-निविदाएं आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपरोक्त वेबसाइट पर 24.04.2025 को 11.00 बजे तक इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड की जानी चाहिए। निविदाएं (केवल तकनीकी बिड) इसी दिन 11.00 बजे के बाद खोली जाएंगी। संयुक्त जोड़िम करार फार्म: संयुक्त जोड़िम करार फार्म को इस निविदा में मांग लेने की अनुमति है। निविदाकारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना: 1. निविदा संबंधी सभी कार्य संपूर्णतः केवल ई-टेंडरिंग के माध्यम से ही किया जाएगा। निविदा प्रस्तुत करने वाले सभी निविदाकारों को पहले आईआईटीएस की वेबसाइट http://www.iimps.gov.in पर रजिस्टर करना होगा। 2. भावी निविदाकारों को सूचित किया जाता है कि अपना ऑफर इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करने से पहले, वे निविदा से जुड़ी नियम व शर्तें, पात्रता मापदंड आदि शिक्कण ध्यानपूर्वक पढ़ लें। 3. निविदा दस्तावेज तथा समय-समय पर जारी होने वाले शुद्धि-पत्र उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। यदि इस निविदा में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो निविदा खुलने की तारीख से कम-से-कम 15 दिन पहले इस बारे में वेबसाइट पर जानकारी दी जाएगी। किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिए / उपरोक्त पते पर अथवा उप मुख्य अभियंता (निर्माण) / जुड़नगर पनवेल, उप मुख्य अभियंता (निर्माण) / पनवेल का कार्यालय, मध्य रेलवे, चौथा माला, बालाजी आंगन के सामने, ओरीजन मॉडल के बगल में, पनवेल-410206, मो.-8828119252 पर किसी भी कार्य दिवस को 10.00 बजे से 17.30 बजे के बीच संपर्क किया जा सकता है।	
असुरक्षित तथा अनाधिकृत रूप से रेल लाइन के पास कार्य करना दंडनीय अपराध है।	

बृहन्मुंबई महानगरपालिका	
सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग	
सावित्रीबाई फुले माता बाल एमसीजीएम अस्पताल, मलाड ईस्ट रिडि गार्डन एमसीजीएम मैटरनिटी होम, पी/एन वार्ड रुचि की अभिव्यक्ति का विज्ञापन	
विषय: सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग पी/एन वार्ड सावित्रीबाई फुले माता बाल एमसीजीएम अस्पताल (रिडि गार्डन एमसीजीएम मैटरनिटी होम), मलाड ईस्ट के अंतर्गत एनजीओ के माध्यम से श्रेणी 'डी' में रिक्त पदों को भरने के संबंध में।	
सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, आर सेंटरल वार्ड, सावित्रीबाई फुले माता बाल एमसीजीएम अस्पताल (रिडि गार्डन एमसीजीएम मैटरनिटी होम), मलाड ईस्ट एनजीओ के माध्यम से अनुबंध के आधार पर श्रेणी 'डी' में रिक्त पदों को भरने के लिए इच्छुक हैं (उनके सदस्यों को रोजगार मिलना चाहिए)। हम आवेदक से अनुरोध कर रहे हैं कि वह अपनी पात्रता तैयार करें और नौकरी के लिए आवेदन करें। आवेदन पत्र पी/उत्तर वार्ड, सावित्रीबाई फुले माता बाल एमसीजीएम अस्पताल (रिडि गार्डन एमसीजीएम मैटरनिटी होम), मलाड ईस्ट दिनांक 26.03.2025 से 28.03.2025 तक सुबह 10.30 बजे से दोपहर 01.30 बजे तक उपलब्ध हो सकता है।	
इच्छुक संगठनों को अधिक जानकारी के लिए पी/उत्तर वार्ड, सावित्रीबाई फुले माता बाल एमसीजीएम अस्पताल (रिडि गार्डन एमसीजीएम मैटरनिटी होम), मलाड ईस्ट से संपर्क करना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 28.03.2025 (दोपहर 01.30 बजे तक) है। बताए गए कार्यालय अवधि के बाद दाखिल किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। कृपया ध्यान दें।	
हस्ता/-	
चिकित्सा अधिकारी	
सावित्रीबाई फुले माता बाल एमसीजीएम अस्पताल, मालाड पूर्व (रिडि गार्डन एमसीजीएम मैटरनिटी होम), पी/एन वार्ड	
पीआरओ/2914/विज्ञा./2024-25	
समय पर उपचार, बचाएं प्राण।	

आधी-अधूरी खुशी

हाल में जारी ‘हैप्पीनैस इंडेक्स’ में भारत की स्थिति में कुछ सुधार की बात तो जरूर सामने आयी है,लेकिन हमारी खुशी के सूचकांक को यूक्रेन, फिलीस्तीन, नेपाल व पाक से पीछे बताना गले नहीं उतरता। खुशी के मानक निर्धारण के जो पैमाने पश्चिमी देशों द्वारा इस्तेमाल किये जाते हैं, उनकी विश्वसनीयता व तार्किकता को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। निस्संदेह, हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। हमारी प्रगति की राह पर सदियों की गुलामी के दर्श अभी पूरी तरह मिटे नहीं हैं। निस्संदेह, देश में गरीबी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई है, सामाजिक सुरक्षा में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। लेकिन तबाह हो चुका फिलीस्तीन, युद्ध में बर्बाद यूक्रेन व दुनिया में मदद मांगता फिरता पाकिस्तान खुशी के मामले में हम से आगे नहीं हो सकते। भले ही देश में आर्थिक विषमता हो, पूंजी का केंद्रीयकरण चंद हाथों में हो, लेकिन इसके बावजूद हम दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती आर्थिकी हैं। लेकिन इसके बावजूद दर्शाए खुशी के सूचकांक सरकारों को आईना दिखाते हैं कि हर नागरिक की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो, सामाजिक सुरक्षा मिले, काम के अवसर मिलें। मंथन हो कि हमारी रीति-नीतियों में कहां खोटा रह गयी कि हम कथित खुशी के सूचकांक में गरीब मुल्कों के पीछे दर्शाए जा रहे हैं। हर राष्ट्रवादी व्यक्ति को ये बात चुभती है कि उसका देश खुशी के मानकों में पिछड़े देशों से भी क्यों पिछड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुश देश बताया जा रहा है। इसी कड़ी में डेनमार्क व स्वीडन भी हैं। ये विकसित देश भारत के एक शहर जितनी आबादी वाले देश हैं। इनके यहां साक्षरता दर ऊंची है व समृद्ध संसाधन उपलब्ध हैं। कहते भी हैं छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। हमारे देश में प्रांतीय, जातीय व धार्मिक अस्मिता के नाम पर जनसंख्या बढ़ाने की दलीलें दी जा रही हैं। दुहाई दी जाती है कि हमारा धर्म इजाजत नहीं देता कि परिवार नियोजन अपनाया जाए। संसाधन सीमित हैं और खाने वाले मुंह लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी शासन-प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार एक हकीकत है, जिसको लेकर तमाम राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े समय-समय पर आते रहते हैं। भ्रष्टाचार का मतलब है कि किसी के वाजिब हक का मारा जाना। शिक्षा,स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में हम यदि पिछड़े हैं तो कहीं न कहीं ये हमारे नीति-नियंताओं की विफलता भी है। यह हमारे लोकतंत्र की भी विडंबना है कि मतदान का अधिकार रखने वाले चुनाव के दौरान योग्य प्रतिनिधियों के चयन से चूकते हैं। यही वजह कि जनप्रतिनिधि संस्थाओं में दागदार नुमाइंदों की उपस्थिति बढ़ती जा रही है। जब ऐसे तत्व हमारे भाग्य-विधाता बनेंगे तो खुशी कहां से आएगी? स्पष्ट है कि यदि हम खुशी के मानकों में खरे नहीं उतरे हैं तो नीतियां बनाने वालों को आत्ममंथन करना होगा। जागरूक नागरिक व जिम्मेदार राजनीतिक नेतृत्व तसवीर बदल सकता है।

शख्सियत

नंदा

भारतीय फिल्म अभिनेत्री



नंदिनी कर्नाटकी (8 जनवरी 1939 -25 मार्च 2014), जिन्हें नंदा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेत्री थीं जो हिंदी और मराठी फिल्मों में दिखाई दीं।भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक मानी जाने वाली उनका करियर 30 साल से अधिक का है। वह छोटी बहन, धूल का फूल, भामी, काला बाजार, कानून, हम दोनों, जब जब फूल खिले, गुमनाम, इतफाक, द ट्रेन और प्रेम रोग में अपने अभिनय के लिए जानी जाती हैं।

नंदा का जन्म एक महाराष्ट्रीयन शो-बिजनेस परिवार में विनायक दामोदर कर्नाटकी (मास्टर विनायक) के घर हुआ था, जो एक सफल मराठी अभिनेता-निर्माता-निर्देशक थे। मास्टर विनायक भारतीय फिल्म उद्योग की कई हस्तियों से जुड़े थे। उनके भाई वासुदेव कर्नाटकी एक छायाकार थे जबकि प्रसिद्ध फिल्म हस्तियां बाबूराय पेंढारकर (1896-1967) और भालजी पेंढारकर (1897-1994) उनके सौतेले भाई थे। वह महान फिल्म निर्देशक वी. शांताराम के मामा भी थे। मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के अच्छे दोस्त थे और उन्होंने लता मंगेशकर को अपनी फिल्म पहिली मंगलागौर से फिल्म उद्योग में पेश किया था । फिल्मों में शामिल होने के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई और उन्हें घर पर ही प्रसिद्ध स्कूल शिक्षक और बॉम्बे स्काउट्स कमिश्नर गोकुलदास वी. माखी ने कोचिंग दी। उनके एक भाई मराठी फिल्म निर्देशक जयप्रकाश कर्नाटकी हैं, जिनकी शादी अभिनेत्री जयश्री टी. से हुई है नंदा ने 1948 में मंदिर से अपनी शुरुआत की। सिल्वर स्क्रीन पर उन्हें पहली बार रबेबी नंदाइ के रूप में पहचाना

गंभीर पहल से ही सुलझेगा मणिपुर संकट

आखिरकार, भाजपा और उसके जरिए, भारत सरकार ने पिछले कुछ समय से मणिपुर में फैली अव्यवस्था को सुलझाने की दिशा में कुछ निर्णायक कदम उठाए हैं। सरकार ने पहले एक अनुभवी नौकरशाह को राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया, फिर भाजपा शासित मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को पद छोड़ने को कहा और चार दिन बाद 13 फ़रवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ये सभी कदम एक साथ और जल्दी-जल्दी उठाए गए। लेकिन काफी वक्त से यह लंबित था। स्वयं भाजपा और राज्य में भाजपा सरकार उम्मीद के विपरीत आस लगाए हुए थी कि 3 मई, 2023 को राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद से सरकार ने जो कमजोर कदम उठाए हैं, उनसे मामले सुलझ जाएंगे। बीच-बीच में कुछ समय के लिए शांति काल के अलावा लंबे समय तक टकराव अनवरत जारी रहा। इसके चलते मैतेई और कुकी जातियों के बीच संबंध बहुत तनावपूर्ण हो गए। समस्या कई अन्य कारणों से भी बढ़ गई, जिसके विभिन्न पहलुओं पर गंभीर प्रभाव पड़े। दो कारण भाजपा को ठोस कदम उठाने से रोक रहे थे: एक तो यह कि हम एक लोकतंत्र हैं, दूसरा यह कि राज्य में भी सत्ता उसी दल के पास थी, जिसकी केंद्र में सरकार है। ऐसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पार्टी के लिए शर्मिंदगी की वजह बनता क्योंकि इसका मतलब होगा कि खुद अपनी ही पार्टी की सरकार के कामकाज पर सवाल उठना। इसके अलावा, पार्टी को ऐसा उत्तराधिकारी मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया जो सभी को स्वीकार्य हो। हालांकि,

जीवन मंत्र

किसी भी लक्ष्य को एक निर्धारित समय-सीमा में हाँधने से जीवन-शक्ति को एक दिशा मिल जाती है, परंतु इसके लिए कुछ कल्पना भी आवश्यक है। प्रायः व्यक्ति काल्पनिक नहीं होता, फंस जाता है और अंततः हताश हो जाता है।

श्री

कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, 'तुम मुझे बहुत प्रिय हो।' फिर कहते हैं कि तुम्हें समर्पण करना होगा। समर्पण की शुरुआत एक धारणा से होती है। पहले तुम्हें मानना होगा कि तुम ईश्वर के प्रिय हो, तब समर्पण स्वतः होता है। किसी भी लक्ष्य को एक निर्धारित समय-सीमा में बांधने से जीवन-शक्ति को एक दिशा मिल जाती है, परंतु इसके लिए कुछ कल्पना भी आवश्यक है। प्रायः व्यक्ति काल्पनिक नहीं होता, फंस जाता है और अंततः हताश हो जाता है। परंतु यदि

सत्तारूढ़ पार्टी ने अब कड़वा घुंंट पीना तय कर लिया है। देर आयद दुरुस्त आयद ! भविष्य की ओर देखते हुए, बहुत काम किए जाने की जरूरत है। सबसे पहले, समस्या की उत्पत्ति को देखें ताकि इससे निपटने में मदद मिल सके। म्यांमार में सैन्य शासन यानी जुंटा का अपने देश के संपूर्ण भूभाग पर, खासकर मणिपुर सीमा से लगते इलाके पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं है। इन क्षेत्रों में कई समूह अपनी सरकार से युद्धरत हैं और यहां तक कि कुछ इलाका उनके अधीन भी है। इसके अलावा, हिंसा के कारण, गोल्डन ट्राइंगल नाम से कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय ड्रग व्यापार रूट पर, मुख्य रूप से मोरेह शहर और मणिपुर के क्षेत्र से होकर गुजरने वाला, असर हो रहा था क्योंकि म्यांमार में अफीम की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कमी आई थी या विस्तार नहीं हो पाया था। कई कुकी और संबंधित जनजातियां अपने स्थानीय रिश्तेदारों को मदद से मणिपुर में, मुख्य रूप से कुकी बहुल चूड़ाचांदपुर क्षेत्र में आन बसे और उन्होंने मणिपुर में भी अफीम उगाना शुरू कर दिया। स्थानीय लोग भी इस मुनाफेदार खेती में उनके साथ लग गए। जब यह बात राज्य सरकार के संज्ञान में आई, तो अवैध अप्रवासियों की पहचान करने के लिए कार्रवाई की गई। स्थानीय लोग,जिसकी पीठ पर बहुत अफीम एवं ताकतवर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया का हाथ था,इस कार्रवाई का विरोध करने लगे। वे सरकार को पीछे हटने को मजबूर करना चाहते थे। उनके सौभाग्य से -और राज्य के दुर्भाग्य से- मैतेइयों को अनुसूचित



जनजाति का दर्जा दिए जाने वाली याचिका पर, मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा आए आदेश की गलत व्याख्या ने परेशानी पैदा करने का एक कारण प्रदान किया। 27 मार्च, 2023 को जारी इस आदेश में कहा गया था :‘राज्य में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले पर शीघ्रता से विचार किया जाना चाहिए’। इसमें केवल याचिका पर विचार करने के लिए आदेश था, न कि मैतेइयों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए। लेकिन कुकियों ने जानबूझकर इसे गलत ढंग से प्रस्तुत किया, यह कहते हुए कि मैतेइयों को एसटी का दर्जा दे दिया गया है। हालांकि बाद में उच्च न्यायालय ने इस पैराग्राफ को हटा दिया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। दोनों पक्षों ने रैलियां निकालनी शुरू कर दीं, कुछ हिंसा भी बढ़की और दोनों समुदायों द्वारा नाकेबंदी और जवाबी नाकेबंदी होने लगी। मैतेई बहुल घाटी में और कुकी एवं अन्य संबंधित जनजाति बहुल पहाड़ी इलाके में। स्थिति बदतर

बी.एल. वोहरा

होती चली गई। हालात इतने खराब हो गए कि घाटी के लोग चूड़ाचांदपुर नहीं जा सकते थे और इसके विपरीत चूड़ाचांदपुर वाले घाटी में नहीं आ सकते। कुकियों ने एक अलग प्रशासन की मांग की। वे नहीं चाहते थे कि मैतेई लोगों को एसटी का दर्जा मिले क्योंकि उन्हें लगा कि इससे न केवल उनकी नौकरी का कोटा प्रभावित होगा बल्कि मैतेई लोग वैध तरीके से पहाड़ियों में जमीन भी खरीद सकेंगे। इसलिए, दोनों समुदायों के बीच एक तरह से पूर्ण पैमाने पर जातीय संघर्ष छिड़ गया, जिसमें हिंसा के कारण जान-माल का नुकसान हुआ और दोनों पक्षों के लोगों को विस्थापित होना पड़ा। आरोप है कि ड्रग माफिया ने अपनी मोटी जेबों के दम पर इस स्थिति को और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाई है। जल्द ही, सरकार और उसकी मशीनरी तक भी हिंसा का असर हो गया। दुर्भाग्यवश, दोनों समुदायों के बीच इस तरह का दोफाड़ कुछ हद तक पुलिस सहित सरकारी अमले

समर्पण और जिम्मेदारी



ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम जितना अधिक समर्पित होते हो, उतने ही अधिक जिम्मेदार होते हो। जो गैर-जिम्मेदार है, वह समर्पण नहीं कर सकता। कोई गैर-जिम्मेदार क्यों है? वह या तो आलसी है या भयभीत, या दोनों ही। यदि तुम आलसी और भयभीत हो, तो तुम प्रेम में नहीं रह सकते। पूर्ण जिम्मेदारी ही पूर्ण समर्पण है। इसे स्वीकार करना थोड़ा कठिन है, परंतु यही वास्तविकता है। प्रायः लोग कहते हैं, 'मैं जिम्मेदारी लेता हूं' या 'मैं समर्पित हूं', पर मैं कहता हूं कि ये दोनों साथ-साथ चलते हैं। यदि तुम ज्ञान के प्रति समर्पित हो, तो तुम ज्ञान को फैलाने के लिए प्रतिबद्ध होते हो। तुम जिम्मेदारी लेते हो कि ज्ञान की

जीवन ऊर्जा

गणेश शंकर विद्यार्थी: निधन 25 मार्च 1931

देहावसान

समस्त मानव जाति का कल्याण हमारा परमोद्देश्य है



इस समय, देश में धर्म की धूम है। उत्पत्त किये जाते हैं, तो धर्म और ईमान के नाम पर और ज़िद की जाती है, तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ पासी और बुद्ध मिर्था धर्म और ईमान को जानें, या न जानें, परंतु उसके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता-बुझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं, उधर जुत जाता है। यथाथ दोष है, कुछ चलते-पूरजे, पड़े-लिखे लोगों का – जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार,

सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ बिजाना शाजापुर मध्य प्रदेश



आत्मा के शुद्धीकरण का जिम्मा हम स्वयं लें

ज

लता हुआ दीपक शुभ का प्रतीक है वहीं जब कभी जलता हुआ कोई दीपक बुझ जाता है तो उसे अशुभ का संकेत माना जाता है और मन भयग्रस्त हो जाता वास्तव में जब हम मन से निर्बल होते हैं तो ऐसे नकारात्मक भाव हमें आकर घेर लेते हैंमन ऐसी विपरीत शंकाओं से घिरकर व्यकुल हो उठता



पंडित कैलाशचंद्र शर्मा

वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचारक व सर्व सिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ के संस्थापक। मो. नं. 9425980556

तभी संभव होगा जब आत्मा के शुद्धीकरण का जिम्मा हम स्वयं अपने ऊपर ले लें इसके लिए साधना में रत रहना होगा जब आप सामने वाले पर नाराज होते हैं तो स्वयं को भी उसी कष्ट से पीड़ित करते हैं क्योंकि गुस्सा करने वाला ज्यदा प्रभावित होता है जिस पर आप गुस्सा कर रहे हैं यह उस पर निर्भर करता है कि वह उसे ग्रहण करे या न करे ऐसी स्थिति में आप अपने पैरो पर कुल्हाड़ी मार लेते हैंअतः आप नित्य ही मन में सकारात्मक विचारों का उच्चारण करें कि आज मैं फलोंफलों कार्य करके सबको खुश करूंगा जो दूसरों की खुशी की परवाह करता वह ईश्वर की सबसे अनमोल कृति का दर्जा प्राप्त करता है वह स्वयं के लिए अपने आप ही सापर से मोती चुन लेने के बराबर कार्य में सिद्धि हासिल कर लेता है यह अनमोल उपहार उसे अनायास ही प्राप्त हो जाता है।

उद्योगी पुरुष को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है



आकर्षित हो जाता है मन को योगी बनाये बिना जीवन को निरोगी भी नहीं बनाया जा सकता है। मन आलस्य और प्रमाद में सुख मानता है इसलिए आलसी बना रहता है जिस दिन वह परिश्रम के सुख का स्वाद चख लेगा उस दिन इसके द्वारा स्वतः ही आपको परिश्रम के लिए प्रेरित किया जायेगा। आलस्य और सुख दे सकता है, लेकिन भविष्य को दुःखमय बना देगा और परिश्रम वर्तमान के कष्ट दे सकता है, लेकिन भविष्य को आनंदमय बना देगा प्रयास करो कि आपका मन भोग में नहीं योग में लगे आलस्य में नहीं परिश्रम में लगे और नश्वर को ही नहीं शाश्वत सुख को भी प्राप्त करे।

यह अखबार "माध्यम कार्पोरेट सर्विसेज लि. " के लिए प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक अरुण लाल द्वारा ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के. के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001 से प्रकाशित एवं सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं. 4, एन.के.इंडस्ट्रियल इस्टेट, इनसाइड प्रवासी इंडस्ट्रियल इस्टेट गेट नं. 2, गोरगांव पू., मुंबई-63 से मुद्रित। फोन नं. 022-66555719 ईमेल : indiagroundreport@gmail.com कार्यकारी संपादक : अनित बृज (पी.आर.बी. अधिनियम के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार) ।

ऐसे कि शनि लगनेश होता है साथ ही द्वितीयभाषापर भी होता है, अब शनि लगनेश और द्वितीय भावपर होकर किसी तरह के रजयोग में बैठे या किसी अन्य तरह से शुभ स्थिति में बैठे हों, जैसे मकर लग्न में शुक्र पंचम और दशम भावपर होकर बेहद शुभ और सफल कारक ग्रह होता है शनि शुक्र के साथ संबंध बनाकर बलि स्थिति में शुक्र भावपर बैठे तब जब भी शनि या शुक्र की महादशा का समयकाल आएगा या किसी लग्नभाषारी ग्रह की महादशा के समय शनि या शुक्र का अंतर आया तब जीवन में सफलता आदि रजयोग तुल्य सुख मिलेगा और समयकाल काफी अच्छा चलेगा ॥

महादशाओं का ऐसे ग्रहों की मिलना परम अच्छा होता है जीवन के लिए क्योंकि महादशा लंबे समयकाल की स्थिति आती है ज्यादातर ग्रहों की साथ ही जितने ज्यादा ग्रहों की स्थिति अनुकूल होंगी और उनकी दशाएँ मिलेंगी समयकाल उसी अनुसार दशाएँ से ज्यादा अच्छा आती है या चरता रहता है ॥

ओबीसी आरक्षण के साथ होगा नगर निकाय का चुनाव



रांची: झारखंड में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर ओबीसी आरक्षण के साथ ही 48 नगर निकायों में चुनाव कराया जाएगा। विधानसभा में 24 मार्च को सरयू राय के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में मंत्री सुदिव्य कुमार सौनू ने यह बात कही है। सरकार के इस रुख से निकाय चुनाव में और विलंब होना तय है। मंत्री का कहना है कि रांची, कोडरमा और देवघर को छोड़कर शेष 21 जिलों में ट्रिपल टेस्ट के तहत डोर-टू-डोर सर्वे का काम पूरा हो चुका है। प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा के लिए आयोग की टीम क्षेत्रों का भ्रमण कर रही है।

शिक्षा विभाग ने 10225 शिक्षकों का किया तबादला

पटना। शिक्षा विभाग ने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि बिहार में 1 लाख 90 हजार के शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था। लंबे समय से ये शिक्षक इंतजार कर रहे थे। कई महीनों बाद जाकर आज विभाग शिक्षकों पर मेहरबान हुई है। विभाग ने सोमवार को 10,225 शिक्षकों की लिस्ट जारी की है। जिन 10225 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है, उनका स्कूल आवंटन नहीं हुआ है। सिर्फ जिले का नाम अभी आया है। दरअसल वैसे शिक्षक/शिक्षिकाओं से स्थानांतरण के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन मांगा गया था जो विशेष समस्या से पीड़ित थे। प्रेस रिलीज में बताया गया कि 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन किया, इसमें से 51,284 शिक्षकों ने इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर हेतु आवेदन किया है। जिन शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है उन्हें स्कूलों का आवंटन 10 04 12025 से 20 04 12025 तक किया जायेगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी सूची में बताया गया है असाध्य रोग (कैंसर) से ग्रसित 113 पुरुष शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था। इसके अलावा 113 महिला शिक्षकों ने भी इसी समस्या के कारण ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था। इसके अलावा किडनी रोग, हाट और लीवर के रोग से ग्रसित कुल 937 महिला और पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है। दिव्यंगता के आधार पर कुल 2685, परिवार में मानसिक रूप से परेशान सदस्यों के लिए आवेदन करने वाले 573 का ट्रांसफर किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि यदि शिक्षकों द्वारा ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दिये गए अभ्यावेदन एवं घोषणा पत्र में किसी भी प्रकार का गलत सूचना दिया गया है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सभी स्थानान्तरित शिक्षकों को जो जिला आवंटित किए गए हैं, उसे वे स्वीकार करते हैं।

तब्बलीगी जमात से जुड़े 10 नेपाली नागरिकों को किया गया डिपोर्ट



मोतिहारी : राजस्थान में पकड़े गए तब्बलीगी जमात के 10 नेपाली नागरिकों को पूर्वी चंपारण जिला के रक्सौल बॉर्डर से डिपोर्ट किया गया है। हालांकि, राजस्थान पुलिस ने स्थानीय इमीग्रेशन, एसएसबी और थाना पुलिस को इस मामले की जानकारी भी नहीं दी तथा इनको इसकी भनक भी नहीं लगी। डिपोर्ट किए गए दस नेपाली नागरिकों में पांच महिला और पांच पुरुष हैं। इनपर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 47 वीं बटालियन पनटोका कैप के डिप्टी कमांडेंट दीपक कुशान ने बताया कि, "राजस्थान पुलिस द्वारा 10 नेपाली नागरिक को छोड़े जाने की जानकारी नहीं दी गई है। इमीग्रेशन विभाग को भी राजस्थान पुलिस की इस कार्रवाई की जानकारी नहीं है।" वहीं रक्सौल थानाध्यक्ष भी राजस्थान पुलिस की कार्रवाई से अनभिज्ञ हैं। मिली जानकारी के अनुसार, तब्बलीगी जमात से जुड़े 10 नेपाली नागरिकों को राजस्थान के दौसा पुलिस ने पकड़ा था। जिसमें पांच पुरुष और उनकी पत्नियां शामिल थीं। ये सभी विगत चार मार्च को रक्सौल बॉर्डर से भारत में प्रवेश कर राजस्थान पहुंचे। सभी पांच पुरुष पापड़दा इलाके के एक मस्जिद में रह रहे थे। वही उनकी पत्नी दौसा के अलग-अलग घरों में रह रही थीं।



स्मार्ट लैब से विदेशी मुद्रा की हर चाल पर नजर

- » धन शोधन और आतंकी फंडिंग से भी उठ सकता है पर्दा
- » लैब का निर्माण आर्थिक अपराधों पर प्रहार के लिए हुआ

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) द्वारा विकसित स्मार्ट लैब अब मुद्रा की हर चाल पर नजर रखेगी। यह अत्याधुनिक लैब धन शोधन और आतंकी फंडिंग से जुड़े मामलों का पर्दाफाश करने में सक्षम है। भारत आने वाले यात्रियों द्वारा लाई गई विदेशी मुद्रा का पूरा विवरण करेंसी डिक्लरेशन फॉर्म (सीडीएफ) में भरा जाता है। एफआईयू इस डेटा का विश्लेषण कर यह पता लगाने में सक्षम है कि कौन कितनी बार विदेशी मुद्रा के साथ भारत आया और उसका उद्देश्य क्या था।

टैक्स चोरी और एफसीआएर उल्लंघन पर भी नजर

एफआईयू के अनुसार, यह लैब विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआएर) के तहत गैरकानूनी धन के उपयोग, टैक्स चोरी और अन्य वित्तीय फर्जीवाड़ों पर भी पैनी नजर रख रही है।

आधुनिक फंड फ्लो ट्रूल देगा पूरी जानकारी

स्मार्ट लैब में मौजूद फंड फ्लो ट्रूल बैंक खातों में जमा और निकासी का बारीकी से विश्लेषण कर सकता है। यह ट्रूल विभिन्न वित्तीय संस्थानों के बैंक स्टेटमेंट को एक समान फॉर्मेट में बदलकर संदिग्ध लेनदेन को उजागर करता है।

तकनीक से होगा तेजी से विश्लेषण

इस ट्रूल में पायथन और पलास्क जैसी अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे मिनटों में यह पता चल सकता है कि धन कहां से आया, कब आया और कहां भेजा गया।

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार सोमवार को लगातार छठे कारोबारी दिन मजबूती के साथ बंद हुआ। इस तेजी के चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पिछले 7 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। निफ्टी 6 फरवरी के बाद पहली बार 23,600 के पार बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 78,000 अंक के स्तर को पार करने में सफल रहा।

संसेक्स 77,984 और निफ्टी 23,658 पर बंद

सभी सेक्टरल इंडेक्स में तेजी

आज के कारोबार में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, रियल्टी, बैंकिंग, एनर्जी, आईटी, आंथ्रल एंड गैस, ऑटो, टेक, एफएमसीजी, हेल्थकेयर और मेटल सेक्टर के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखी गई। बीएसई मिडकैप इंडेक्स 1.32% बढ़कर बंद हुआ स्मॉलकैप इंडेक्स 1.17% की तेजी के साथ बंद हुआ।

बाजार में जोरदार तेजी, निवेशकों को 5.19 लाख करोड़ रुपये का फायदा

बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 418.49 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो शुक्रवार को 413.30 लाख करोड़ रुपये था। शेयर बाजार में आई मजबूती से निवेशकों की संपत्ति में 5.19 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ।

सोने से भी तेज दौड़ी चांदी

नई दिल्ली। सोने की बढ़ती कीमतों के साथ-साथ चांदी की चमक भी निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कोटक सिंक्रोटीज के कमांडिटी रिसर्च विशेषज्ञ कायनात चैनवाला के अनुसार, यदि तेजी जारी रही तो कॉमेक्स चांदी 40 डॉलर प्रति औंस तक जा सकती है, जबकि एमसीएक्स पर इसकी कीमत अगले 3-4 महीनों में 1,25,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंचने की संभावना है। विश्लेषकों के अनुसार, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, चीन में मांग में सुधार और औद्योगिक क्षेत्र में तेजी चांदी के दाम को और ऊपर ले जा सकती है। साल 2024 की पहली तिमाही में चांदी ने 15% रिटर्न दिया है, जो इसे एक मजबूत निवेश विकल्प बनाता है।

23 प्रमुख मुद्रों की पहचान कर उनके समाधान पर चर्चा की गई। बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत पांच परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जो इन राज्यों में ईएसआईसी अस्पतालों से जुड़ी हैं। इनका उद्देश्य बीमति नागरिकों और उनके परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना है।

बिहार, ओडिशा और बंगाल में 63,858 करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा

नई दिल्ली। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के परियोजना निगरानी समूह (PMG) ने बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 19 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की है। इस परियोजनाओं की कुल लागत 63,858 करोड़ रुपये से अधिक है। बैठक में

है। इसके अलावा, इस्पात, कोयला, सड़क परिवहन, पेट्रोलियम, रेलवे और बिजली मंत्रालयों की परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में बिहार के बक्सर में 1320 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट (लागत: 10,439.09 करोड़ रुपये) को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई।

मीशो 8,300 करोड़ का IPO लाएगी

- » जल्द फाइल कर सकती है ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स
- » 85,500 करोड़ हो सकती है वैल्यूएशन

मुंबई। डोमेक्सिट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो इस साल के आखिर तक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO ला सकती है। कंपनी इसके जरिए एक बिलियन डॉलर (करीब 8300 करोड़ रुपये) जुटाना चाहती है। मीशो यह फंडिंग 10 बिलियन डॉलर (करीब 85,500 रुपये) के वैल्यूएशन पर उठाएगी। कंपनी कुछ हफ्तों में इसके लिए ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स भी फाइल करने वाली है। इस बात की जानकारी मनीकंट्रोल ने दी है। रिपोटर्स के मुताबिक, मीशो ने इसके लिए मॉर्गन स्टेनली, कोटक महिंद्रा कैपिटल और सिटी को अपना IPO एडवाइजर बनाया है। इस साल सितंबर-अक्टूबर के बीच स्टॉक एक्सचेंजों लिस्टिंग होने की उम्मीद है।

दो राउंड में करीब 4,705 करोड़ फंडिंग ले चुकी है मीशो



कंपनी टोटल 50 मिलियन डॉलर (करीब 4705 करोड़ रुपये) का फंडिंग उठा चुकी है। इसी साल की शुरुआत में मीशो ने टाइगर ग्लोबल, थिंक इन्वेस्टमेंट्स और मार्स ग्रोथ कैपिटल जैसे निवेशकों से लगभग \$250-\$270 मिलियन (करीब 2300 करोड़ रुपये) का फंड जुटाया था। तब कंपनी की वैल्यूएशन \$3.9-4 बिलियन डॉलर (करीब 34,242 करोड़ रुपये) रहा।

एक साल में 97% कम हुआ मीशो का लॉस

वित्त वर्ष 2023-24 में मीशो ने 7,615 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। यह पिछली वित्त वर्ष के मुकाबले 33% ज्यादा है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी ने 5,735 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। इस दौरान कंपनी का नेट लॉस 97% घटकर 1,569 करोड़ रुपये से 53 करोड़ रुपये पर आ गया। 2024 के आखिर में मीशो प्लेटफॉर्म के ऑर्डर में सालाना आधार पर 35% बढ़ोतरी हुई। कंपनी के प्लेटफॉर्म से 17.5 करोड़ ग्राहकों ने शॉपिंग की। इसमें से मीशो को खरीदने के प्रस्ताव पर विचार करेगा।

आईईडी के सुरक्षा घरे में 60 से ज्यादा नक्सली

22 ग्रामीणों की जा चुकी है जान, 26 सुरक्षाकर्मी घायल

एजेंसी | रांची

चाईबासा में नक्सलियों द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए जमीन के अंदर लगाए गए आईईडी सुरक्षा बलों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। जैसे-जैसे सुरक्षा बल नक्सलियों के करीब पहुंच रहे हैं, वैसे-वैसे विस्फोट की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। अकेले मार्च 2025 में विस्फोट की तीन घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें पांच जवान घायल हुए हैं, जबकि सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं।

सुरक्षा बल भी निशाने पर

झारखंड के कोल्हान इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच निर्णायक लड़ाई चल रही है। कोल्हान की जंग पुलिस बहुत पहले ही जीत जाती, लेकिन नक्सलियों द्वारा जंगल क्षेत्रों में अपनी सुरक्षा के लिए लगाए गए आईईडी बम अब तक इस जंग को जीतने में बाधा बने हुए हैं। नवंबर 2022 से अब तक कोल्हान में आईईडी बमों के विस्फोट से 26 सुरक्षाबल घायल हो चुके हैं। इनमें 209 कोबरा बटालियन के इंस्पेक्टर प्रभाकर साहनी, हवलदार अलख दास, मुकेश कुमार सिंह, अजय लिंडा, भरत सिंह राय, फारूकी शाहरुख खान, वीरपाल सिंह, प्रिंस सिंह, अमरेश सिंह, सौरभ कुमार, संतोष और चिरंजीव पात्रे विस्फोट में घायल हुए हैं। सभी को आनन-फानन में एयरलिफ्ट कर रांची ले जाया गया। अधिकांश जवान अपनी चोटों से उबर चुके हैं लेकिन कई अभी भी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। कोल्हान में सीआरपीएफ के कई जवान भी घायल हुए हैं, जिनमें इंशार अली, राकेश कुमार पाठक, पंकज कुमार यादव और संजीव कुमार शामिल हैं। 22 मार्च को हुए विस्फोट में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए थे, जबकि हेड कान्टेबल गर्ग घायल हुए थे।



नवंबर 2023 से अब तक 22 ग्रामीणों की मौत कोल्हान में सुरक्षा बलों के बाद सबसे ज्यादा नुकसान ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है, नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी में विस्फोट होने से अब तक 24 ग्रामीणों की जान जा चुकी है, जबकि 14 गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

बेहद खतरनाक हैं ये इलाके

चाईबासा के जराइकेला, रेंगरा, टोटो, सोनुया, जेटैया, गुदरी और तुबाहाटा ऐसे इलाके हैं, जहां जंगलों में कदम-कदम पर नक्सलियों ने मौत का साजो-सामान बिछा रखा है। इन वन क्षेत्रों में विस्फोटों के कारण पिछले डेढ़ साल में 22 ग्रामीणों की जान जा चुकी है। हालात ऐसे हैं कि बाइक से जंगल में अभियान पर निकलने वाले जवान भी आईईडी बमों का शिकार बन रहे हैं।

हवाला के पैसों से तो नहीं चल रहे अवैध मदरसे!

धामी सरकार ने दिए जांच के आदेश

एजेंसी | देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित मदरसों की जांच तेज कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई में अब तक 136 मदरसे सील किए जा चुके हैं, जबकि रिपोर्ट के अनुसार, 500 से अधिक अवैध मदरसों के संचालन की जानकारी मिली है। अब सवाल यह उठ रहा है कि इन मदरसों की फंडिंग कहाँ से आ रही थी। प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि जांच रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी जाए।

अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई

देहरादून जिला प्रशासन ने 24 मार्च को सहस्रपुर के एक मदरसे में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। उक्त मदरसे ने बिना अनुमति के एक अतिरिक्त मंजिल का निर्माण किया था।



प्रदेश में अवैध मदरसों, मजारों और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध रूप से बड़े पैमाने पर मदरसों का संचालन गंभीर विषय है। जिसकी जांच के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। - पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

फंडिंग की होगी विस्तृत जांच

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में करीब 450 पंजीकृत मदरसे हैं, जो शासन को अपनी वित्तीय जानकारी देते हैं। लेकिन बिना मान्यता के चल रहे 500 से अधिक मदरसों की आर्थिक स्रोतों की जांच के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि इन अवैध मदरसों को धन कहां से मिल रहा है।

69000 शिक्षक भर्ती मामला अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास घेरा

एजेंसी | लखनऊ



69000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने जोरदार नारेबाजी की और सरकार पर अनियमितताओं का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण हजारों आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार नौकरी से वंचित रह गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस

मामले में अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन सरकार ने अब तक इसका पालन नहीं किया, जिससे मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

अभ्यर्थियों की मांग: सुप्रीम कोर्ट में हो तोस पैरवी

प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी कृष्ण चंद्र ने बताया कि रहमारी मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखे और जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करे। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी है, लेकिन सरकार अब तक अपने रुख को स्पष्ट नहीं कर रही।

8 साल 'बेमिसाल' लेकिन 5 साल 'बेहाल'

अभ्यर्थियों ने सरकार पर जानबूझकर मामले को लटकाने का आरोप लगाया। अमरेंद्र पटेल ने बताया कि 2018 में शुरू हुई यह भर्ती प्रक्रिया लगातार विवादों में रही। 13 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने तीन महीने के भीतर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने इस फैसले को लागू नहीं किया और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि वह सुप्रीम कोर्ट में तोस पैरवी करे और उनके हक की नौकरी दिलाए।

जफर अली की गिरफ्तारी के बाद सपा सांसद की बड़ी मुश्किलें

जियाउर्रहमान बर्क को पुलिस भेजेगी नोटिस

एजेंसी | संभल

जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद अब सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस सपा सांसद को विवेचना में शामिल होने के लिए 41A का नोटिस देने की तैयारी में है। हिसा से जुड़े केस में सांसद नामजद अभियुक्त हैं, इसलिए उनके बयान होने जरूरी हैं। बता दें कि संभल में बीते साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ था, जिसमें चार लोगों की मौत हुई थी। 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल सहित 40 नामजद और 2750 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

हिंसा मामले में 80 गिरफ्तार



पुलिस अब तक इस मामले में 80 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि 74 आरोपियों के पोर्ट्रेट चरखा किए गए हैं। बीते 23 मार्च को संभल पुलिस ने जामा मस्जिद के सदर जफर अली एखौकैट को संभल हिंसा मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, इसके बाद उन्हें आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने 2 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा दिया। संभल एसपी कृष्ण कुमार विशनोई ने बताया कि थाना कोतवाली संभल में 24 नवंबर की हिंसा मामले में केस दर्ज किया गया है। रविवार को जफर अली गिरफ्तारी की गई। हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार, विवेक द्वारा सांसद को 41 ए का नोटिस दिया जाएगा। जिससे उनसे पूछताछ हो सके। उन्होंने बताया कि सांसद नामजद अभियुक्त हैं इसके आधार पर उनका बयान होना जरूरी है। उनकी अन्य व्यक्तियों से क्या बात हुई, दंगा कैसे भड़का, यह सब पूछताछ में जरूरी है।

आईपीएल 2025

गिल के सामने होगी अख्यर की चुनौती

नए कप्तान के साथ विजयी शुरुआत करने उतरेगी पंजाब

एजेंसी | अहमदाबाद

पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 में अपने अभियान की शुरुआत गुजरात टाइटंस के खिलाफ करेगी। इन दोनों ही टीमों का प्रदर्शन पिछले सीजन अच्छा नहीं रहा था। गुजरात 2022 सीजन की विजेता रही है, लेकिन पंजाब फ्रेंचाइजी ने कभी भी आईपीएल का खिताब नहीं जीता है। पंजाब इस बार नए कप्तान के साथ उतरेगी और उसकी कोशिश विजयी शुरुआत करने की होगी। पंजाब ने श्रेयस अख्यर को टीम का कप्तान बनाया था जिसके नेतृत्व में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने पिछले सीजन खिताब अपने नाम किया था। इस बार श्रेयस के सामने पंजाब को विजेता बनाने की चुनौती होगी। श्रेयस आईपीएल में सफल कप्तानों में गिने जाते हैं। उन्होंने केकेआर को खिताब दिलाने से पहले 2020 सीजन में दिल्ली कैपिटल्स को अपनी कप्तानी में फाइनल में पहुंचाया था, लेकिन टीम उस वक्त विजेता नहीं बन सकी थी। अब उनका लक्ष्य पंजाब का आईपीएल खिताब जीतने का 18 साल लंबा इंतजार खत्म करना होगा।

पंजाब को पहले खिताब की तलाश

पंजाब उन फ्रेंचाइजी में शामिल है जो करीब आकर भी ट्रॉफी नहीं जीत सकी है। पंजाब आईपीएल 2018 के सेमीफाइनल में पहुंचा था, जबकि उसने 2014 में फाइनल में जगह बनाई थी। 35 वक्त फाइनल में केकेआर ने उसे हराया था, लेकिन पिछले चार वर्षों में पंजाब की टीम शीर्ष पांच में भी जगह नहीं बना सकी है। किंग्स इलेवन पंजाब से पंजाब किंग्स बनने के बावजूद इस टीम को अब भी अपने पहले आईपीएल खिताब का इंतजार है।

पिछली गलतियों से गुजरात को लेनी होगी सीख

दूसरी तरफ, भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान शुभमन गिल के लिए गुजरात के कप्तान के तौर पर पिछला सीजन अच्छा नहीं रह था और टीम अंक तालिका में आठवें स्थान पर रही थी। गुजरात ने 2022 में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खिताब जीता था और 2023 में उपविजेता रही थी। लेकिन पिछले गुजरात ने अपना कप्तान बदला और गिल को जिम्मेदारी सौंपी।



गिल-अख्यर में होगी जंग

इस मैच में गिल और अख्यर के बीच जंग देखने मिलेगी जो हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का हिस्सा थे। दोनों ही बल्लेबाज शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। अख्यर ने जहां भारत की तरफ से टूर्नामेंट में सर्वाधिक 243 रन बनाए, वहीं गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच में शतक ठोका था और आगे भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ होंगे।

गिल-बटलर करेंगे शुरुआत

गुजरात के पास गिल और इंग्लैंड के जोस बटलर के रूप में आदर्श सलामी जोड़ी है। मध्यक्रम की कमान वेस्टइंडीज के शेरफेन रदरफोर्ड, साई सुदर्शन और मसूद शाहरुख खान के हाथों में होगी, जबकि ऑलराउंडर राशिद खान, राहुल तेवतिया, ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर और महिलावा लोमरोर से योगदान की उम्मीद है। गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज अपना प्रभाव छोड़ना चाहेंगे। तेज गेंदबाजी विभाग में उनके साथ देने के लिए कैगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, दक्षिण अफ्रीका के गेराल्ड कोएन्जे और अनुभवी इशांत शर्मा जैसे अच्छे गेंदबाज शामिल हैं। गुजरात के स्पिन विभाग की जिम्मेदारी फिर से राशिद खान निभाएंगे।

IPL 2025 के लिए दोनों टीमों का स्क्वाड

गुजरात टाइटंस: राशिद खान, शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, शेरफेन रदरफोर्ड, अरशद खान, ग्लेन फिलिप्स, करीम जनत, महिलावा लोमरोर, निशांत सिंधु, साई किशोर, वाशिंगटन सुंदर, अनुज रावत, जॉस बटलर (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र, जेराल्ड कोएन्जी, गुरनूर बराड़, इशांत शर्मा, जयंत यादव, कागिसो रबाडा, कुलवंत खेजरोलिया, मानव सुभार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

पंजाब किंग्स: श्रेयस अख्यर (कप्तान), युजवेंद्र चहल, अशदीप सिंह, शाशंक सिंह, प्रभसिमरन सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन, नेहाल वडेरा, ग्लेन मैक्सवेल, प्रियांश आर्या, जोश इंग्लिश, अजमतुल्लाह ओमारजई, लॉकी फर्ग्युसन, वैशाक विजयकुमार, यश ठाकुर, हर्षीत बरार, अरोन हार्डी, विष्णु विनोद, कुलदीप सेन, सूर्याश रोहड़ा, मुशीर खान, हरनूर पन्नू, जेवियर बार्टलेट, पाल्या अविनाश, प्रवीण दुबे।

मियामी ओपन जोकोविच और राडुकानू प्री-क्वार्टर फाइनल में



एजेंसी | फ्लोरिडा

सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और ग्रेट ब्रिटेन की एमा राडुकानू मियामी ओपन के प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इस जीत के साथ ही जोकोविच एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट्स में 411 जीत के आंकड़े पर पहुंच गए हैं। चौथी वरीयता प्राप्त सर्बियाई खिलाड़ी जोकोविच ने अर्जेंटीना के कैमिलो उगो कैराबेली को 6-1, 7-6, (7-1) से पराजित किया। जोकोविच ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहला सेट मात्र 34 मिनट में जीत लिया

और दूसरे सेट में जल्दी ही ब्रेक ले लिया। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने जोकोविच ने टाई-ब्रेक के बाद कैराबेली को 7-1 से हराकर अपनी जीत पक्की की। महिला एकल में राडुकानू अमेरिका की मैक्कार्टिनी केसलर के मैच से हटने से वांकओवर के साथ प्री-क्वार्टर में पहुंच गईं। जब 25 वर्षीय केसलर मुकाबले से हटीं, तब राडुकानू 6-1, 3-0 से आगे थीं। उनके अलावा चौथी वरीय अमेरिका की जेसिका पेगुला और अर्मांडा अनीसिमोवा भी प्री-क्वार्टर में पहुंच गई हैं।

राफा को पछाड़ा

एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में 411वीं जीत के साथ वह राफेल नडाल से आगे निकल कर सर्वकालिक सूची में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। सातवें मियामी ओपन खिताब की तलाश में 37 वर्षीय खिलाड़ी जोकोविच अंतिम 16 में इटली के लोरेंजो मुसेट्टी से भिड़ेंगे। मुसेट्टी ने कनाडा के फेलिक्स ऑगर अलियासिमे को 4-6, 6-2, 6-3 से हराकर

अगले दौर में जगह बनाई। दूसरी ओर, नौवीं वरीयता प्राप्त यूनान के स्टेफानोस सितसिपास, 24वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्दो से 7-6 (7-4) 6-3 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। एक अन्य मुकाबले में बुल्गारिया के त्रिगोर दिमित्रोव ने रूस के कारेन खचानोव को 6-7 (7-3) 6-4, 7-5 से शिकस्त दी।

सुमित रेड्डी का संन्यास

राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व पदक विजेता रह चुके हैं सुमित



नई दिल्ली। भारत के युगल शटलर और 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मिश्रित रजत पदक विजेता टीम के सदस्य बी सुमित रेड्डी ने सक्रिय बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में संन्यास ले लिया है। अब वह सारा ध्यान कोचिंग पर केंद्रित करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह घोषणा की। हैदराबाद के 33 वर्षीय खिलाड़ी ने पुरुष युगल में मनु अत्री के साथ

जोड़ी बनाई। फिर अपनी पत्नी एन सिकी रेड्डी सहित कई खिलाड़ियों के साथ मिश्रित युगल भी खेला। सुमित और मनु की करियर की शीर्ष विश्व रैंकिंग 17 रही। दोनों ने 2016 दक्षिण एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता, रियो ओलिंपिक के लिए क्वालीफाई किया और हैदराबाद में एशिया टीम चैंपियनशिप में पुरुष टीम का भी हिस्सा थे।

कबड्डी महासंघ पर लगा प्रतिबंध हटेगा

नई दिल्ली। भारतीय कबड्डी खिलाड़ियों को राहत देते हुए खेल की अंतरराष्ट्रीय शासी संस्था अगले महीने राष्ट्रीय महासंघ पर लगा निलंबन हटाने जा रही है। अदालत द्वारा नियुक्त प्रशासक ने कार्यभार निवाचित संस्था को सौंप दिया है। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ (आईकेएफ) के अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी ने सोमवार को बताया कि अगले महीने होने वाली कार्यकारी परिषद की बैठक के बाद प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। तिवारी ने कहा, एकेएफआई पदाधिकारियों ने जेएलएन स्टेडियम में कार्यालय से काम करना शुरू कर दिया है। इसलिए एकेएफआई पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा।

हरमनप्रीत, मंधाना और दीप्ति शीर्ष श्रेणी में बरकरार

एजेंसी | नई दिल्ली

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, उप कप्तान स्मृति मंधाना और हरफनमौला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को ग्रेड ए में बरकरार रखा गया है, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के केंद्रीय अनुबंध की सर्वोच्च श्रेणी है। बोर्ड ने 16 अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची सोमवार को जारी की। तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर, ऑलराउंडर जेमिमा रोड्रिग्स, विकेटकीपर ऋचा घोष और सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को भी ग्रेड बी में बनाए रखा गया है। लेकिन पिछले साल ग्रेड बी में शामिल बाएं हाथ की स्पिनर राजेश्वरी गायकवाड अपना अनुबंध बरकरार नहीं रख पाईं। युवा ऑफ स्पिनर श्रेयांका पाटिल, तेज गेंदबाज टियास साधु और अरुंधति रेड्डी, ऑलराउंडर अमनजोत कौर और विकेटकीपर उमा छेत्री को पहली बार केंद्रीय अनुबंध में शामिल किया गया है। उन्हें यास्तिका पाटिया, राधा यादव, स्नेह राणा और पूजा वस्त्राकर के साथ ग्रेड सी में शामिल किया गया है।



हरलीन को नहीं मिली जगह

जिन खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध में जगह नहीं मिल पाईं उनमें मेघना सिंह, देविका वैद्य, सब्बिनेनी मेघना, अंजलि सरवाना और हरलीन देयोल शामिल हैं। केंद्रीय अनुबंध में ए श्रेणी में शामिल महिला क्रिकेटर को सालाना 50 लाख, बी श्रेणी की क्रिकेटर को 30 लाख और सी श्रेणी की क्रिकेटर को 10 लाख रुपए मिलते हैं।

डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय सिंह बने UWW-एशिया के ब्यूरो सदस्य

अम्मान (जॉर्डन)। भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह को सोमवार को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) एशिया का ब्यूरो सदस्य चुना गया। यह चुनाव एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की शुरुआत से एक दिन पहले अम्मान में UWW-एशिया की आम सभा के दौरान हुआ। WFI के अनुसार, संजय सिंह ने 38 में से 22 मत हासिल किए, जिससे एशियाई कुश्ती समुदाय का मजबूत समर्थन झलकता है। इस प्रतिष्ठित पद पर उनका चुनाव भारतीय कुश्ती के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इस चुनाव से अंतरराष्ट्रीय कुश्ती मंच पर भारत की उपस्थिति और मजबूत होगी।



पेरेंट्स बने अथिया-राहुल

बॉलीवुड अभिनेत्री अथिया शेट्टी के घर नहीं परी ने जन्म लिया है। अथिया ने अपनी बेटी के आगमन की खुशी को अपने फैस के साथ साझा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह खबर दी, जिसके बाद उनके चाहने वालों में उत्साह की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर अथिया ने साझा की पोस्ट अथिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक संक्षिप्त और भावुक संदेश के जरिए घर के नए सदस्य के आगमन की जानकारी दी। उनकी इस घोषणा के बाद फैस और इंडस्ट्री के दोस्तों ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया। यह उनके और उनके पति केएल राहुल के लिए बेहद खास पल है। कई फिल्मी हस्तियों ने दी बधाई इस खबर के सामने आते ही कई फिल्मी सितारों ने अथिया और केएल राहुल को बधाइयां दीं। मृणाल ठाकुर ने पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए लिखा, 'बधाई'। इसके साथ उन्होंने लाल दिल वाले इमोजी भी साझा किए। वहीं, शनाया कपूर, कियारा आडवाणी, टाइगर श्राफ, भूमि पडनेकर, कृति सेनन, सोफी चौधरी समेत कई सितारों ने भी इस पोस्ट को देखकर अपनी खुशी व्यक्त की।



नहीं रहे 'भाबीजी घर पर हैं' के लेखक मनोज संतोषी

'भाबीजी घर पर हैं', 'हप्पू की उलटन-पलटन', 'जीजा जी छत पर' और 'मैडम मैं आई कम इन' जैसे धारावाहिकों के लेखक मनोज संतोषी का निधन हो गया है। काफी समय से वह लीवर की बीमारी से ग्रसित थे। हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में मनोज का इलाज चल रहा है, जहां उन्होंने बीती रात अंतिम सांस ली। मनोज का पार्थिव शरीर आज देर रात हैदराबाद से बुलंदशहर के रामघाट ले जाया जाएगा। पार्थिव शरीर अलीगढ़ से होकर जाएगा।

गायक बनना चाहते थे मनोज

मनोज का जन्म बुलंदशहर में गंगा किनारे बसे कस्बा रामघाट में 1976 में हुआ था। वह बचपन से एक गायक बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मुंबई का रुख किया। हालांकि, मुंबई में मनोज की मुलाकात एक लेखक से हुई, जिसके बाद उन्होंने लेखक बनने का फैसला लिया। मनोज के निधन से हर कोई गमगीन है। टीवी शो में भी मातम पसर गया है। कविता कौशिक से सौम्या टंडन तक, कई सितारों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है।



'छोरी' के सीक्वल का ऐलान

अभिनेत्री नुसरत बरूचा की फिल्म 'छोरी' 26 नवंबर, 2021 को OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला, वहीं समीक्षकों ने भी फिल्म की कहानी को काफी सराहा। प्रशंसक पिछले काफी समय से 'छोरी' के सीक्वल की मांग कर रहे थे। आखिरकार लगभग 4 साल बाद 'छोरी' के सीक्वल का ऐलान हो गया है। इसके साथ फिल्म का पहला पोस्टर भी सामने आ गया है।

विशाल फुरिया कर रहे निर्देशन

नुसरत ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर 'छोरी 2' का पोस्टर साझा किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'कुछ भयावहताएं दबी रहने से इनकार करती हैं... कुछ लौट रहा है।' फिल्म में नुसरत एक बार फिर साक्षी के किरदार में दिखाई देंगी। उनके साथ अभिनेत्री सोहा अली खान भी नजर आएंगी। 'छोरी 2' के निर्देशन की कमान विशाल फुरिया ने संभाली है। फिल्म की कहानी भी इन्होंने ही लिखी है।



'लुसफिर' से भिड़ने आज टिकट खिड़की पर उतरेगा 'सिकंदर'



बॉक्स ऑफिस पर लक्ष्मण उतेकर निर्देशित 'छावा' की रफार बरकरार है। फिल्म ने रिलीज के 38वें दिन तक 583.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इसमें से हिंदी में 567.75 करोड़ और तेलुगु में 15.50 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। कम लागत में बनी जान अग्राहम की 'द डिप्लोमैट' ने 25 करोड़ रुपये की कमाई कर यह साबित कर दिया कि दमदार कंटेंट वाली फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर टिक सकती हैं। अब अगला बड़ा मुकाबला सलमान खान की 'सिकंदर' और मोहनलाल की 'एल 2 एम्युरान' के बीच होने जा रहा है। 'एल 2 एम्युरान' की एडवॉस बुकिंग शानदार रही है।

पत्रलेखा-प्रतीक गांधी ने दिखाया महात्मा ज्योतिराव-सावित्रीबाई का संघर्ष

हाल ही में फिल्म 'फुले' का ट्रेलर रिलीज हुआ है। यह फिल्म एक बायोग्राफिकल ड्रामा है। इस फिल्म के ट्रेलर में अभिनेत्री पत्रलेखा, अभिनेता प्रतीक गांधी, महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी सावित्रीबाई फुले के किरदारों में नजर आ रहे हैं। ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले किस प्रकार समाज में क्रांति लेकर आए, उन्होंने महिलाओं, दलितों के लिए बदलाव की राह तैयार की, इन्होंने बातों की झलक ट्रेलर में नजर आती है। फिल्म का 'ट्रेलर' दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ाने में कामयाब नजर आता है। अनंत महादेवन द्वारा निर्देशित फिल्म 'फुले' में प्रतीक गांधी ने ज्योतिराव फुले और पत्रलेखा ने उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले की भूमिका निभाई है। किस प्रकार से समाजक सुधारक ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने महाराष्ट्र के पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं, विधवाओं और दलितों के जीवन को बदला। इसी बात की झलक फिल्म के ट्रेलर में नजर आती है। यह फिल्म महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती के मौके पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की रिलीज डेट 11 अप्रैल 2025 रखी गई है।

'फुले' का ट्रेलर जारी



न्यूज़ ग्रीफ

संसदीय कार्य मंत्रालय में कोई आरटीआई और लोक शिकायत लंबित नहीं

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्रालय में 2024 के अंत तक कोई आरटीआई और कोई लोक शिकायत का मामला निपटान के लिए लंबित नहीं था। संसदीय कार्य तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरगन ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। इसमें बताया गया कि वर्ष 2025 में 17 मार्च तक मंत्रालय को 57 आरटीआई और 333 लोक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से सभी का निपटारा कर दिया गया है।

सज्जन कुमार के खिलाफ सुनवाई 14 अप्रैल तक टली

नई दिल्ली। राजउ एवेन्यू अदालत ने सोमवार को 1984 सिख विरोधी दंगों के जनकपुरी से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार की सुनवाई टाल दी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 अप्रैल को तय की है। इस मामले में सोमवार को सज्जन कुमार का बयान दर्ज होना था, लेकिन कार्यवाही को आगे बढ़ा दिया गया। गौरतलब है कि अदालत ने 25 फरवरी को सरस्वती विहार दंगा मामले में सज्जन कुमार को उप्रकैद की सजा सुनाई थी। 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान 1 नवंबर को जनकपुरी में सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या कर दी गई थी। वहीं, विकासपुरी इलाके में गुरुचरण सिंह को ज़िंदा जला दिया गया था। 2015 में विशेष जांच समिति (SIT) ने इन मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू की। 2018 में सज्जन कुमार का पॉलिग्राफ टेस्ट भी किया गया था। अब अदालत इस मामले में 14 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगी।

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गवाह को मिल रही धमकी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गवाही देने वाले एक चर्मदीद गवाह को धमकाए जाने के आरोप के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को मामले की जांच करने की अनुमति दी। मामले में गवाह ने आरोप लगाया था कि उसे पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ गवाही देने के कारण धमकाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यूपी पुलिस को निर्देश दिया कि वह इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच करें। साथ ही अपनी रिपोर्ट में पहले से निकाले गए निष्कर्षों से प्रभावित हुए बिना मामले की समीक्षा करें। अदालत ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़े, तो पुलिस एक नई स्थिति रिपोर्ट दायित्व कर सकती है।

आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़

अनंतनाग। अनंतनाग जिले के एक जंगल में सुरक्षाबलों ने एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। इसका इस्तेमाल आतंकवादी रसद अट्ठे के रूप में कर रहे थे। यहां से 200 खाली एके कारतूस, दो गैस सिलेंडर, एक चीनी ग्रेनेड, एक नाइट विजन डिवाइस (एनवीडी), बिस्तर, नाहन और खाने के पैकेट बरामद किये गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस ठिकाने का भंडाफोड़ विशेष अभियान समूह (एसओजी) अनंतनाग, सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने संगलान जंगल के ऊंचे इलाकों में उत्तरसू पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में किया। पुलिस ने कहा कि विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर सुरक्षाबलों ने घने जंगल क्षेत्र में गहन तलाशी अभियान चलाया, जिससे इस ठिकाने का पता चला। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि इसका इस्तेमाल आतंकवादी रसद अट्ठे के रूप में कर रहे थे।

देश में बढ़ रहे छात्रों की खुदकुशी के मामले

सुप्रीम कोर्ट ने बनाई टास्क फोर्स

एजेंसी । नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के बीच बढ़ रहे आत्महत्याओं के मुद्दे पर विचार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस रवींद्र भट की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स शैक्षणिक संस्थानों आईआईएम, एम्स, आईआईटी, एनआईटी और अन्य विश्वविद्यालयों में जातिगत प्रताड़ना के आरोपों की जांच करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया जांच का आदेश

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 में दिल्ली IIT के दो छात्रों की मौत उनकी मृत्यु आईआईटी दिल्ली परिसर में 2023 में हो गई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि दोनों छात्र अनुसूचित जाति समुदाय से आते थे और इस कारण उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। याचिका में ये भी आशंका जताई गई है कि छात्रों की हत्या की गई है। याचिका में कहा गया है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

IIT दिल्ली में हुई थी छात्रों की मौत

दोनों याचिकाकर्ताओं के बेटे आईआईटी दिल्ली में बी.टेक के छात्र थे और उन्हाकी मृत्यु आईआईटी दिल्ली परिसर में 2023 में हो गई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि दोनों छात्र अनुसूचित जाति समुदाय से आते थे और इस कारण उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। याचिका में ये भी आशंका जताई गई है कि छात्रों की हत्या की गई है। याचिका में कहा गया है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।



एजेंसी । नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार अपना बजट पेश करने वाली है। इस बजट से दिल्लीवालों को काफी उम्मीदें हैं। मंगलवार को जब सीएम रेखा गुप्ता बजट पेश करेंगी तो सबकी नजरें दिल्ली को मिलने वाले तोहफों पर रहेंगी। गौरतलब है कि सीएम दीपा सिन्हा की सरकार ने बीजेपी सरकार ने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाने साधे हैं।

राज्यसभा में मुस्लिम आरक्षण पर हंगामा, कार्यवाही स्थगित

एजेंसी । नई दिल्ली

कर्नाटक विधानसभा में मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने के प्रावधान वाला विधेयक पारित होने पर राज्यसभा में सोमवार को सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध जताया। बीजेपी ने कांग्रेस पर संविधान बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया, जिससे सदन में भारी हंगामा हुआ और कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में नेता और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, सरदार पटेल और डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस तेलंगाना और कर्नाटक में एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकार छीनकर मुस्लिमों को आरक्षण दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीके शिवकुमार का बयान संविधान बदलने की कांग्रेस की मंशा को उजागर करता है।

कैश कांड में फंसे जस्टिस वर्मा का हुआ तबादला

वकीलों के विरोध के बाद भी भेजे गए इलाहाबाद हाई कोर्ट

एजेंसी । नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट रजिस्ट्री ने आधिकारिक रूप से घोषणा की थी कि जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया है। यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJ) देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना के निर्देश के बाद लिया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस वर्मा को किया डिरेक्टर

इससे पहले जज यशवंत वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट ने डिरेक्टर कर दिया था। तत्काल प्रभाव से उनसे न्यायिक काम छीन लिया गया। ये फैसला तब लिया गया, जब उनके घर पर 14 मार्च, 2025 को आग लगी थी। आग लगने के बाद घर में बहुत सारा कैश मिला। जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि नकदी उनकी या उनके परिवार की नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह घटना उनकी छवि खराब करने की साजिश का हिस्सा है। वहीं, जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में करने को लेकर वहां के वकील विरोध कर रहे हैं। सोमवार को हाई कोर्ट के वकीलों ने लंब के बाद सांकेतिक हड़ताल भी की। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी की अध्यक्षता में एक आम सभा हुई।

टोल वसूली में धांधली

टोल ऑपरेटरों पर निगाह नहीं रख पा रही एनएचएआई

टोल प्लाजा 1000 से ज्यादा, निगरानी केवल 100 की

देश में पिछले पांच साल में टोल प्लाजा की संख्या हुई दो गुनी

एजेंसी । नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे में फास्टेक के रूप में लगभग शत-प्रतिशत (98 प्रतिशत) इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के बावजूद लचर निगरानी के कारण न तो अनावश्यक दैरी की समस्या खत्म हो पाई है और न ही गड़बड़ियों पर रोक लगाई जा सकी है। स्थिति यह है कि केवल 10 प्रतिशत टोल प्लाजा ही नियमित यानी 2437 निगरानी की सुविधा से लैस हैं और अभी इसके प्रभाव को लेकर कोई रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं हुई है। देश में पिछले पांच साल में टोल प्लाजा की संख्या लगभग दो गुनी हो गई, लेकिन इसके अनुरूप निगरानी के ऐसे उपाय नहीं किए जा सके हैं जो टोल प्लाजा पर लोगों के प्रतीक्षा समय की रियल टाइम जानकारी दे सकें। सरकार ने विश्व बैंक के एक अध्ययन के आधार पर बताया है कि फास्टेक प्रणाली पर अमल के कारण एक वाहन के लिए औसत प्रतीक्षा समय घटकर 47 सेकेंड आ गया, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर टोल ऑपरेटरों की कमजोर प्रणाली के कारण यह स्थिति अभी बहुत दूर है।

आज आरणा दिल्ली सरकार का बजट

संपत्ति कर को लेकर राहत का इंतजार

दिल्ली चुनाव में हुई करारी हार से आम आदमी पार्टी ने बड़ा सबक लिया है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने पिछले महीने यह ऐलान किया कि दिल्ली के लोगों को हाउस टैक्स में बड़ी राहत दी जाएगी। AAP की स्थानीय सरकार ने फैसला लिया कि साल 2024-25 का हाउस टैक्स भरने वाले दिल्ली के मकान मालिकों का पिछला पूरा बकाया माफ कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं अगर वे इस साल हाउस टैक्स जमा कर देते हैं तो उन्हें नए वित्तीय वर्ष में भी छूट दी जाएगी। AAP के इस ऐलान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार पर भी दिल्लीवालों को संपत्ति कर में कोई बड़ा ऐलान करने का दबाव नजर आ रहा है।

बिजली-पानी पर छूट को लेकर हो ऐलान

दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में दिल्लीवालों को 200 युनिट तक फ्री बिजली का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा दिल्ली के लोगों को हर महीने 20 हजार लीटर पानी प्रति परिवार के हिसाब से फ्री दिया जाता है। लोगों को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कम से कम इस योजना को आगे लागू रखेगी। हालांकि, चुनाव के समय भी बीजेपी ने इन योजनाओं को जारी रखने की बात कही थी।

आंध्र प्रदेश में हाथियों का आतंक

अब तक 11 की गई जान

एजेंसी । पार्वतीपुरम

आंध्र प्रदेश के मन्यम जिले में हाथियों का आतंक जारी है। इससे स्थानीय लोगों को अपने गांवों पर हाथियों के हमले का डर सता रहा है। हालांकि अधिकारियों ने पहले हाथियों को ओडिशा वापस खदेड़ने के लिए ऑपरेशन गज्जा शुरू किया था, लेकिन एक हाथी की मौत के बाद ऑपरेशन को बीच में ही रोक दिया गया। यहां तक कि एक झुंड

फसलों को भारी नुकसान

दिसंबर 2024 तक हाथियों ने 3,305 एकड़ में फैली फसलों को नष्ट कर दिया था। 2025 में 630 एकड़ और फसलें नष्ट हो गईं। अधिकारियों ने अब तक 3 तीन करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है। सलूरु और कुरुपम की सीमा में जंधिकोडा और जेके पाडु में विशेष हाथी क्षेत्र बनाने की योजना तैयार की गई थी। इसके लिए लगभग 1,209 एकड़ वन भूमि की पहचान की गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

गुलाम नबी लोन हत्याकांड

हाइकोर्ट ने आरोपियों के बरी होने के फैसले को बरकरार रखा

एजेंसी । श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने पूर्व शिक्षा मंत्री गुलाम नबी लोन हत्याकांड में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य विरोधाभासों से भरे हुए थे और विश्वास के योग्य नहीं थे।

व्या था मामला?

18 अक्टूबर 2005 को श्रीनगर के तुलसीबाग स्थित सरकारी क्वार्टर में पाकिस्तानी आतंकियों अबू ओसामा और बिलाल उर्फ सलाहूद्दीन ने हमला किया था। आतंकियों का असली निशाना सीपीएम नेता और विधायक एमवाई तारिगामी थे, लेकिन हमलावर गलती से शिक्षा मंत्री गुलाम नबी लोन के आवास में घुस गए, जिससे उनकी हत्या हो गई।

2012 में ट्रायल कोर्ट का फैसला

10 अक्टूबर 2012 को ट्रायल कोर्ट ने विश्वसनीय साक्ष्यों की कमी के आधार पर सैयद शब्बीर बुखारी, शकील अहमद सोफी और मुस्ताक हुसैन अब्दुल को बरी कर दिया था। अभियोजन पक्ष ने इन पर आतंकियों को रसद सहायता देने और लश्कर-ए-तेयबा के ऑपरेशन प्रमुख बिलाल उर्फ सईद सलाहूद्दीन के निर्देशों पर काम करने का आरोप लगाया था। राज्य सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति पुनीत गुप्ता की खंडपीठ ने 20 मार्च को सुनाए गए फैसले में ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा।

आंध्र प्रदेश में हाथियों का आतंक

अब तक 11 की गई जान

एजेंसी । पार्वतीपुरम

आंध्र प्रदेश के मन्यम जिले में हाथियों का आतंक जारी है। इससे स्थानीय लोगों को अपने गांवों पर हाथियों के हमले का डर सता रहा है। हालांकि अधिकारियों ने पहले हाथियों को ओडिशा वापस खदेड़ने के लिए ऑपरेशन गज्जा शुरू किया था, लेकिन एक हाथी की मौत के बाद ऑपरेशन को बीच में ही रोक दिया गया। यहां तक कि एक झुंड

फसलों को भारी नुकसान

दिसंबर 2024 तक हाथियों ने 3,305 एकड़ में फैली फसलों को नष्ट कर दिया था। 2025 में 630 एकड़ और फसलें नष्ट हो गईं। अधिकारियों ने अब तक 3 तीन करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है। सलूरु और कुरुपम की सीमा में जंधिकोडा और जेके पाडु में विशेष हाथी क्षेत्र बनाने की योजना तैयार की गई थी। इसके लिए लगभग 1,209 एकड़ वन भूमि की पहचान की गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

राहुल गांधी की नागरिकता विवाद

गृह मंत्रालय को 4 हफ्ते में फैसला देने का दिया निर्देश

एजेंसी । लखनऊ

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को 4 सप्ताह के भीतर फैसला देने का आदेश दिया है। मंत्रालय ने 8 हफ्ते का समय मांगा था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

क्या है मामला ?

कनाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस विगनेश शिशिर ने इस मुद्दे पर जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता भी है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84(ए) के तहत चुनाव लड़ने की योग्यता का उल्लंघन करता है। यदि यह आरोप साबित होता है, तो उनकी संसदीय रद्द हो सकती है।

केंद्र को पहले ही दी गई थी जानकारी

19 दिसंबर 2024 को हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह 24 मार्च 2025 तक मामले में अपनी कार्रवाई का ब्यौरा पेश करे। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकी। याचिका में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने इसके समर्थन में ब्रिटिश सरकार के 2022 के गोपनीय मेल का हवाला दिया है। अब अदालत के आदेश के

सीबीआई ने एनएचएआई के GM को 15 लाख की रिश्तत लेते पकड़ा

1.18 करोड़ कैश बरामद

पटना। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पटना रीजनल ऑफिस में महाप्रबंधक (GM) रामप्रीत पासवान को 15 लाख रुपये रिश्तत लेते हुए रपे हाथों गिरफ्तार किया है। छापमारी के दौरान सीबीआई को 1.18 करोड़ रुपये नकद भी मिले हैं। सीबीआई लंबे समय से एनएचएआई अधिकारियों की रिश्ततखोरी पर कार्रवाई कर रही है। इससे पहले ही कई अधिकारियों को रिश्तत लेते पकड़ा गया है। जून 2024: सीबीआई ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में एनएचएआई के जीएम पुरुषोत्तम लाल चौधरी को 10 लाख की रिश्तत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इस मामले में 6 अन्य आरोपी भी पकड़े गए थे। मार्च 2024: मध्य प्रदेश में एनएचएआई के जीएम अरविंद काले और इंदौर में नकद वसूली के नाम पर बड़ी धांधली उजागर हुई।

2021 में लागू किए गए नियम पर नहीं हुआ अमल

वाहनों को टोल प्लाजा पार करने में कम से कम दो से तीन मिनट लग जाता है। उस पर एनएचएआई ने हाल में यह नियम वापस ले लिया कि अगर लाइन सी मीटर से लंबी हो जाए तो टोल बैरियर को खुले वाली स्थिति में छोड़ दिया जाना चाहिए। 2021 में लागू किए गए इस नियम पर एक बार भी अमल नहीं हुआ। उल्टे इसके विरोध के कारण सरकार को नियम वापस लेना पड़ा। परिवहन मंत्रालय की ओर से बताया गया कि फास्टेक की फूल-पूफ व्यवस्था के लिए नियमित निगरानी की उद्देश्य से 113 टोल प्लाजा को चुना गया है।

व्यवस्था सुधारने की कोशिश कर रही सरकार

रियल टाइम निगरानी वाले जबकि पंजीक (36) उत्तर प्रदेश में हैं, जबकि आंध्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश के पांच-पांच और दिल्ली का एक टोल प्लाजा रिडिजीट दोला शामिल है। इस रियल टाइम निगरानी के आधार पर सरकार एआई सिस्टम के जरिये टोल प्लाजा की व्यवस्था सुधारने की कोशिश कर रही है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, रियल टाइम निगरानी वाले टोल प्लाजा की संख्या बढ़ाई जा रही है। दैरी व्यावहारिक समस्याओं के कारण होती है।

